माघ कृष्णा - 9 संवत 2081 वर्ष - 12 अंक - 178 पृष्ठ - 8 रु. 5/- चेन्नई » गुरुवार » 23-01-2025 www.dakshinbharat.com Email : chennai@dakshinbharat.com

# दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 गेंदबाजों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार बुमराह

6 युद्ध विराम समझौते का ईमानदारी से पालन जरूरी

7 योगी ने मंत्रियों संग त्रिवेणी में किया अमृत स्नान

## फर्स्ट टेक

### राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी

**नई दिल्ली/भाषा।** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मिशन ने पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किए हैं। गोयल ने बताया कि 2021 से 2022 के बीच लगभग 12 लाख स्वास्थ्य कर्मी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से जुड़े और भारत ने एनएचएम के तहत कोविड-19 महामारी के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी।

### गाजा-मिस्र सीमा पर नियंत्रण बना रहेगा : इजराइल

**यरूशलम/एपी।** इजराइल ने कहा है कि वह हमास के साथ युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफाह सीमा पर नियंत्रण बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में उन खबरों का खंडन किया गया कि फलस्तीनी प्राधिकरण सीमा को नियंत्रित करेगा। इसमें कहा गया है कि हमास से संबद्ध न होने वाले स्थानीय फलस्तीनी सीमा पर केवल पासपोर्ट पर मुहर लगाएंगे। इस युद्ध विराम का चौथा दिन है तथा इससे युद्धग्रस्त गाजा में कम से कम छह सप्ताह के लिए शांति स्थापित होने तथा इजराइल की ओर से बंदी बनाए गए सैकड़ों फलस्तीनी लोगों के बदले में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 लोगों को रिहा किए जाने की उम्मीद है।

### माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे

**डबलिन/एपी।** सांसदों द्वारा गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान किये जाने के बाद बुधवार को माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव में मार्टिन की 'फियाना फेल' पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती थीं, लेकिन उसे इतनी सीट नहीं मिली थी कि वह अपने बलबूते सरकार बना सके। कई सप्ताह की बातचीत के बाद, लंबे समय से प्रभावी दक्षिणपंथी पार्टियां 'फियाना फेल' और 'फाइन गाएल' कई निर्दलीय सांसदों के समर्थन से गठबंधन बनाने पर सहमत हो गईं। समझौते के तहत, मार्टिन (64) तीन साल के लिए प्रधानमंत्री होंगे, जबकि 'फाइन गाएल' के साइमन हैरिस उपप्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद दोनों नेता शेष दो वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने-अपने पद बदलेंगे।

| सूर्यास्त 23-01-2025 | सूर्योदय 24-01-2025 |
|---|---|
| 6:05 बजे | 6:35 बजे |

| BSE | NSE |
|---|---|
| 76,404.99 | 23,155.35 |
| (+566.63) | (+130.70) |

| सोना | चांदी |
|---|---|
| 8,245 रु. | 102,000 रु. |
| (24 कैरेट) प्रति ग्राम | प्रति किलो |

### मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

#### निजता की शुचिता

निजता का अर्थ नहीं यह कि,
हम राष्ट्र विरोधी काम करें।
कर लें मनमर्जी मनमानी,
केवल अपना ही पेट भरें।
निजता की शुचिता आवश्यक,
इस पर थोड़ा सब ध्यान धरें।
अपनी निजता संवर्द्धन हित,
दूजों की निजता नहीं हरें।।

## बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विकसित भारत बनाने में योगदान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/एजेन्सी।** केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)' योजना की 10वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया और कहा कि यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में व्यापक रूप से योगदान देगी।

नड्डा ने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में कमी लाना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि योजना की सफलता समग्र सरकारी दृष्टिकोण से महिलाओं को मुख्यधारा में लाने की नीति में बदलाव पर निर्भर करती है। देश अब महिला विकास से आगे बढ़कर महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ चुका है।

### 'बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ' ने लैंगिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने में अहम भूमिका निभाई : प्रधानमंत्री

**नई दिल्ली/भाषा।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को कहा कि इस पहल ने लैंगिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि बालिकाओं को शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने के अवसर प्राप्त हों। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में आज ही के दिन हरियाणा के पानीपत में इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य घटते शिशु लिंग अनुपात को रोकना और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान है। यह योजना तीन मंत्रालयों- महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

## जलगांव के पास ट्रेन की चपेट में आए पटरी पर उतरने वाले यात्री

### इस हादसे में कम से कम 12 यात्रियों की मौत होने की जानकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**जलगांव/भाषा।** उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम एक ट्रेन में आग की अफवाह के बाद पटरी पर उतरे कुछ यात्री पास की पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। अधिकारियों ने इस हादसे में कम से कम 12 यात्रियों की मौत होने की जानकारी दी है।

विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) दत्तात्रय कराले ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि 12 शव पास के सिविल अस्पताल भेजे गए हैं, जबकि छह से सात लोग घायल हुए हैं।

मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा मुंबई से 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित पचोरा के पास माहेजी और परधाडे स्टेशन के बीच हुआ, जहां शाम करीब पांच बजे लखनऊ-पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के कारण किसी ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। हालांकि, उन्होंने मृतक संख्या की पुष्टि नहीं की।

मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता स्वप्निल नीला ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री पटरी पर उतर गए और बेंगलूरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।

**लखनऊ-पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के कारण किसी ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री पटरी पर उतर गए और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।**

कराले ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, माहेजी और परधाडे स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 372/07 पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की घटना घटी। ट्रेन उसी स्थान पर रुक गई और कुछ यात्री नीचे उतर गए। इस दौरान, वे ट्रेन संख्या 12627 (बेंगलूरु-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस) की चपेट में आ गए। उन्होंने बताया, छह से सात यात्री घायल हुए हैं। सभी घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दोनों ट्रेन अपने अगले निर्धारित स्टेशन पर पहुंच गई हैं और दुर्घटनास्थल से मलबा हटा दिया गया है।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस हादसे के महज 15 मिनट के भीतर दुर्घटनास्थल से रवाना हो गई, जबकि कर्नाटक एक्सप्रेस ने 20 मिनट में आगे की यात्रा शुरू की।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायलों का पचोरा के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और उनमें से ज्यादातर खतरे से बाहर हैं।

## श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**अयोध्या (उप्र)/भाषा।** अयोध्या के राम मंदिर में बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों लोगों ने पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया।

अधिकारियों ने बताया कि राम मंदिर में 'जय श्री राम' के नारों की गूंज के बीच देर शाम तक श्रद्धालुओं का हुजूम रामलला के दर्शन के लिए जन्मभूमि पथ पर उमड़ता रहा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गयी थी।

इससे पहले, ज्योतिषियों ने गत 11 जनवरी को वर्षगांठ की शुभ तिथि निर्धारित की थी। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तीन दिनों तक भव्य कार्यक्रमों के साथ इस अवसर को मनाया।

उस दौरान भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आए थे।

बुधवार को 'अंग्रेजी कैलेंडर' के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। हनुमानगढ़ी में भक्तों की एक किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कतारें लगीं।

इसके अलावा दशरथ महल, कनक भवन और अन्य मंदिरों में भी ऐसी ही भीड़ थी। मणिरामदास छावनी में सुबह रथ यात्रा निकाली गई जो 41 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत थी। इसमें धार्मिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में 1.25 लाख से अधिक 'श्री राम रक्षास्रोत' का जाप करना शामिल है।

## 'भारत को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से खतरा है'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि भारत को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खतरा है। उन्होंने देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकता के महत्व और विभाजनकारी बयानों का मुकाबला करने पर जोर दिया।

डॉ. अब्दुल्ला ने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) मुख्यालय में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ''देश आज भी खुद को बचाने के लिए बलिदान मांग रहा है। भारत को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खतरा है। देश के अंदर के लोग ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें खुद को, अपने भाइयों और बहनों को मजबूत बनाना होगा।''

डॉ. अब्दुल्ला ने विभाजनकारी दुष्प्रचार की आलोचना की, खास तौर पर 'हिंदू खतरे में है' जैसे बयानों की उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा, ''इस देश में 80 प्रतिशत हिंदू हैं, तो खतरा कहां है? इस तरह के बयान का उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना है। इस झूठ को मिटाना हर किसी का कर्तव्य है।'' उन्होंने पूर्व में फैलाए गए ऐसे ही दुष्प्रचार का जिक्र किया और बताया कि कैसे 1996 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से लोगों के बसने के बारे में गलत सूचना फैलाई गई थी। उन्होंने कहा, ''ये दुष्प्रचार फैलाया गया कि वे (पीओके से लोग) आएंगे और आपकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। मैंने बार-बार स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना कोई भी यहां नहीं बस सकता, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।''

## जम्मू-कश्मीर में रहस्यमय बीमारी, चार और लोग अस्पताल में भर्ती

**राजौरी/जम्मू/भाषा।** जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के बडहाल गांव से तीन बहनों समेत चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले डेढ़ महीने में एक रहस्यमय बीमारी ने जिले में 17 लोगों की जान ले ली है। एक केंद्रीय टीम ने बुधवार को भी जिले के तीन परिवारों में हुई इन मौतों के कारणों की अपनी जांच जारी रखी। जांच में शामिल एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि 200 से अधिक नमूने विभिन्न संस्थानों में जांच के लिए भेजे गए हैं। बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद 16 से 22 वर्ष की तीन बहनों को बडहाल से राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसी) में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से बीमार एक अन्य मरीज जावेद अहमद (24) को मंगलवार शाम जीएमसी राजौरी से पीजीआई चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया।

## अगर पुतिन बातचीत नहीं करते हैं तो रूस पर प्रतिबंध संभव : ट्रंप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**वाशिंगटन/भाषा।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से कभी भी मिलने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने आगाह किया कि अगर रूस, यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत के लिए आगे नहीं आता है तो रूस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

यह पूछे जाने पर कि अगर पुतिन बातचीत के लिए आगे नहीं आते हैं तो क्या अमेरिका रूस पर और भी प्रतिबंध लगाएगा तो ट्रंप ने कहा, ''ऐसा ही लगता है।'' ट्रंप ने कहा, ''संघर्ष कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है आपके पास एक सक्षम राष्ट्रपति नहीं

था..., अगर होता तो युद्ध नहीं होता। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन में युद्ध कभी नहीं होता।''

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''रूस कभी यूक्रेन में नहीं जाता। पुतिन और मेरे बीच बहुत अच्छी और मजबूत समझ थी। ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने जो बाइडन का अनादर किया। उन्होंने लोगों का भी अनादर किया। वह स्मार्ट हैं। वह समझते हैं।'' उन्होंने कहा, ''इसके अलावा, पश्चिम एशिया में भी यह सब कभी नहीं होता क्योंकि ईरान काफी कमजोर था। ''

एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह पुतिन से कभी भी मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, ''जब भी वह चाहेंगे, मैं उनसे मिलूंगा। लाखों लोगों की जान जा रही है जिनमें अधिकतर सैनिक हैं... यह एक भयानक स्थिति है। बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और शहर तबाह हो चुके हैं।''

यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखेगा, या वह जल्द ही यह बंद कर देगा, ट्रंप ने कहा कि वह इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हम मामले को देखेंगे। हम (वोलोदिमीर) जेलेंस्की से बात कर रहे हैं। हम बहुत जल्द राष्ट्रपति पुतिन से बात करने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि आगे क्या किया जाता है।''

## भारत का विकास समावेशी और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ होना चाहिए : राजनाथ सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**पथनमथिट्टा (केरल)/भाषा।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत का विकास समावेशी, समतापूर्ण, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और नैतिक रूप से वांछनीय होना चाहिए तथा केंद्र सरकार जलवायु अनुकूल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

सिंह ने कहा कि देश तेजी से विकास कर रहा है और इसलिए इसकी खपत ''आवश्यकता आधारित होना चाहिए न कि लालच आधारित'' और इसके लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमारे व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''इस्तेमाल करो और निपटान करो'' वाली अर्थव्यवस्था को खत्म किये जाने की जरूरत है।

रक्षा मंत्री राज्य के पथनमथिट्टा जिले में कवयित्री, पर्यावरणविद् और मानवाधिकार कार्यकर्ता सुगाथाकुमारी की 90वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक समारोह के समापन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''भारत एक तेजी से विकास करने वाला देश है, लेकिन इसका विकास समावेशी, न्यायसंगत, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और नैतिक रूप से वांछनीय होना चाहिए।'' उन्होंने सुगाथा कुमारी को न केवल एक कवयित्री बल्कि ''समाज की चेतना की रक्षक'' बताया, क्योंकि उनका काम 'भावनात्मक सहानुभूति, मानवतावादी संवेदनशीलता और नैतिक सतर्कता से ओतप्रोत'' था जो सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को उठाने का एक जरिया बन गया।

### केंद्र 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करेगा

**अलप्पुझा/भाषा।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि देश भर में 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित करने का केंद्र सरकार का फैसला भारत में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और देश के समग्र विकास में योगदान देने के उसके प्रयासों का हिस्सा है। केरल के अलप्पुझा में विद्याधिराज सैनिक स्कूल के 47वें वार्षिक दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद राजनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूल में लड़कियों के दाखिले का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कर्मियों को शामिल करने के लिए भारत के हर जिले में सैनिक स्कूल स्थापित करने का फैसला लिया है।

तैयारी

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित 'सेंटिनल्स ऑफ द सी' मोटरसाइकिल अभियान के प्रतिभागी बुधवार को अमृतसर के पास अटारी सीमा पर 49वें स्थापना दिवस से पहले अपनी यात्रा की तैयारी करते हुए।

# भारत 2030 से पहले ही एसडीजी के स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने के पथ पर अग्रसर : सरकार

**नई दिल्ली/भाषा**

केंद्र सरकार ने बुधवार को पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रगति की समीक्षा की और उसे बताया गया कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ भारत 2030 की समयसीमा से पहले अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल को बताया गया कि एनएचएम ने मानव संसाधनों के विस्तार, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों को उजागर करने और स्वास्थ्य आपातकाल के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के वास्ते अपने महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि पिछले तीन वर्षों में, एनएचएम ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोग उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है। मंत्रिमंडल ने एसडीजी के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अगले दो वर्षों के लिए मिशन को जारी रखने की भी मंजूरी दी।

बयान में कहा गया, ''सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ भारत 2030 की समयसीमा से पहले अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है।'' इसमें कहा गया, ''एनएचएम के जारी प्रयासों ने भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है।''

बयान के अनुसार, मिशन के प्रयास विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य सुधारों का अभिन्न अंग रहे हैं और इसने देश भर में अधिक सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल को 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान एनएचएम के तहत प्रगति से अवगत कराया गया।

मंत्रिमंडल को मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में त्वरित गिरावट तथा टीबी, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, तपेदिक, कुष्ठ रोग, वायरल हेपेटाइटिस आदि जैसे विभिन्न रोगों के कार्यक्रमों के संबंध में प्रगति और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसी नई पहलों से भी अवगत कराया गया।

बयान में कहा गया कि एनएचएम की एक प्रमुख उपलब्धि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भीतर मानव संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि रही है। साल 2021-22 में, एनएचएम में 2.69 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल किया, जिनमें सामान्य ड्यूटी मेडिकल अधिकारी, विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स, सहायक नर्स दाइयां, आयुष डॉक्टर, संबद्ध स्वास्थ्यकर्मी और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 90,740 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल किए गए। यह संख्या बाद के वर्षों में बढ़ी और 2022-23 में 4.21 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल किया गया, जिसमें 1.29 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी थे। 2023-24 में 5.23 लाख कर्मचारी शामिल किए गए, जिसमें 1.38 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी थे।

बयान में कहा गया कि इन प्रयासों ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कहा गया कि एनएचएम ढांचे ने खासकर कोविड-19 महामारी से निपटने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं और श्रमिकों के मौजूदा नेटवर्क का उपयोग कर एनएचएम ने जनवरी 2021 और मार्च 2024 के बीच कोविड-19 टीकों की 220 करोड़ से अधिक खुराक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने एनएचएम के तहत प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में भी प्रभावशाली प्रगति की है।

# क्रूज जहाजों के प्रवासी संचालकों के लिए अनुमानित कर व्यवस्था अधिसूचित

नई दिल्ली/भाषा। आयकर विभाग ने क्रूज जहाजों के प्रवासी संचालकों के लिए अनुमानित कराधान व्यवस्था लागू होने की शर्तें निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है।

सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के क्रम में जुलाई में पेश पिछले बजट में क्रूज जहाजों के संचालन में लगे अनिवासी भारतीयों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था पेश की थी।

इसके अलावा भारत में ऐसे जहाजों का संचालन करने वाली कंपनी से पट्टे पर लिए गए जहाजों के किराये से हुई आय पर किसी विदेशी कंपनी को छूट भी दी गई है।

आयकर नियम, 1962 में इस आशय के संशोधनों को मंगलवार को अधिसूचित किया गया है।

इसके अनुसार, इस अनुमानित कराधान व्यवस्था का लागू होना कुछ शर्तों के अधीन है। क्रूज जहाजों के संचालन में लगे प्रवासी व्यक्ति को 200 से अधिक यात्रियों की वहन क्षमता या 75 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले यात्री जहाज को छुट्टियों एवं मनोरंजन के लिए चलाना चाहिए और यात्रियों के लिए उचित भोजन एवं केबिन की सुविधा भी होनी चाहिए।

शर्तों के मुताबिक, प्रवासी व्यक्ति ऐसे जहाज को भारत के कम-से-कम दो समुद्री बंदरगाहों पर मुख्य रूप से यात्रियों को ले जाने के लिए संचालित करे।

## सेना ने लद्दाख में श्योक, नुब्रा घाटियों को जोड़ने के लिए दो 'बेली' पुल बनाए

लेह/जम्मू/भाषा। भारतीय सेना ने बुधवार को श्योक नदी पर दो नवनिर्मित 'बेली' पुलों का उद्घाटन किया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में श्योक और नुब्रा घाटियों के बीच संपर्क बढ़ गया है।

रक्षा प्रवक्ता त्सेरिंग अंगचुक ने बताया कि लेह के दिस्कित उपमंडल में शतसे तकनाक के पास स्थित पुलों का उद्घाटन सियाचिन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर वीएस सलारिया और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के उपाध्यक्ष ने किया। उन्होंने कहा कि 'फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इंजीनियर्स' द्वारा निर्मित ये दो पुल 50 फुट चौड़े और 100 फुट लंबे हैं तथा इनके निर्माण से यात्रा की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाती है।

इन पुलों के निर्माण से नुब्रा और श्योक घाटियों के सबसे दूर के गांवों के लिए यात्रा का समय लगभग दो घंटे कम हो गया है। उद्घाटन समारोह में सैन्यकर्मियों, नुब्रा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल और चरसा, बर्मा, कुरी तथा मुर्गी गांवों के समुदाय के सदस्यों सहित अन्य व्यक्ति शामिल हुए।

रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि ये पुल स्थानीय आबादी के लिए वरदान साबित होंगे, खासकर कड़ाके की सर्दी के दौरान।

अधिकारी ने बताया कि इससे आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा और सियाचिन क्षेत्र के गांवों के लिए बेहतर आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा।

कुंभ — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में भाग लेने के लिए पहुंचे।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को रांची में अपने आवास पर राजी पढाहा सरना प्रार्थना सभा, केंद्रीय समिति और केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधियों से मिले।

## भारत में हरित ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट

नई दिल्ली/भाषा। देश की कुल हरित ईंधन आधारित क्षमता 20 जनवरी तक 217.62 गीगावाट पहुंच गई। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है कि 2024 में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में 24.5 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता में 3.4 गीगावाट की वृद्धि की। इससे 2023 की तुलना में सौर ऊर्जा में दो गुना से अधिक वृद्धि और पवन ऊर्जा में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अगुवा के रूप में उभर रहा है। 20 जनवरी, 2025 तक भारत की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता (हरित ऊर्जा क्षमता) 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2024 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 462 गीगावाट थी, जिसमें से 209.44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा थी। इसमें जलविद्युत भी शामिल है। देश का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।

# यूरोपीय संघ के साथ समझौते से भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश आएगा: जयंत चौधरी

**दावोस/भाषा**

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बुधवार को कहा कि चार यूरोपीय देशों के समूह के साथ नए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते से भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश आएगा और 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे मंत्री ने 'पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय प्रतिभा ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता साबित की है और वैश्विक कंपनियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं भारतीय युवाओं के कौशल में उनके विश्वास को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे के निर्माण व निवेश लाने पर काफी काम किया है और इसके परिणाम हर जगह दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह बंदरगाह हो, रेलवे हो या सड़क व्यवस्था हो।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने कहा कि ये किसी भी उद्योग के साथ-साथ लोगों तथा निवेशकों के लिए बुनियादी चीजें हैं। उन्होंने कहा, '' यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार अपने युवाओं पर बहुत भरोसा करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं युवाओं से बातचीत करते हैं और हर अवसर पर उन्हें प्रेरित करते हैं।'' मंत्री ने हाल ही में आयोजित 'युवा नेता संवाद' का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ छह घंटे बिताए और यह केवल समूचे भारत से आए देश के युवाओं की बात सुनने के लिए किया गया। मंत्री ने कहा कि यह सरकार द्वारा हमारे देश के युवाओं के प्रति अपनाए जा रहे दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव है।चौधरी ने कहा, '' जब हम कौशल विकास की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया अब हमारी युवा प्रतिभा की क्षमता को पहचान रही है। हम विभिन्न शिक्षा व कौशल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं और कुछ स्थानों पर तो हमने अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि कृत्रिम मेधा (एआई) कौशल जैसे क्षेत्रों में भी हम दुनिया में शीर्ष स्थान पर हैं।'' विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान यहां हुई बैठकों के बारे में उन्होंने कहा कि स्विजरलैंड सरकार शीघ्र ही चार यूरोपीय देशों के समूह के साथ व्यापार व आर्थिक भागीदारी समझौते को आकार देगी तथा भारत को उम्मीद है कि यह अगले वर्ष से प्रभावी हो जाएगा। मंत्री ने कहा, '' इसका एक प्रमुख सकारात्मक परिणाम यह है कि यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें कौशल विकास घटक भी शामिल होगा। इन चार यूरोपीय देशों के कौशल विकास संस्थानों और उनके पाठ्यक्रमों को हमारे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि भारत में कोई कौशल सीखने वाले व्यक्ति को इन यूरोपीय देशों में भी मान्यता मिलेगी।'

## सरपंच हत्या में शामिल लोग बख्शे नहीं जाएंगे : शिंदे

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बीड जिले के मासजोग गांव के सरपंच देशमुख का नौ दिसंबर को अपहरण कर हत्या कर दी गयी थी। देशमुख की हत्या के मामले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मिक कराड को मामले से जुड़े जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया था।

# छत्तीसगढ़: गरियाबंद मुठभेड़ में दो और नक्सलियों के शव बरामद, मृतक संख्या बढ़कर 16 हुई

गरियाबंद (छत्तीसगढ़)/भाषा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पिछले दो दिनों में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने बुधवार को दो अन्य नक्सलियों का शव बरामद किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त अभियान के तहत मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों को आज मुठभेड़ स्थल पर तलाश के दौरान दो अन्य नक्सलियों के शव मिले।

पुलिस ने मंगलवार को बताया था कि छत्तीसगढ़-उड़ीसा सीमा पर मैनपुर थाना क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के संयुक्त अभियान में एक करोड़ रुपए के इनामी सीपीआई (माओवादी) नेता समेत चौदह नक्सली मारे गए।

इसी अभियान के दौरान दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक कोबरा और दूसरा उड़ीसा पुलिस के एसओजी का जवान है।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान रामचंद्र रेड्डी उर्फ जयराम उर्फ चलपति के रूप में हुई है, जो सीपीआई (माओवादी) का केंद्रीय समिति का सदस्य था और उस पर एक करोड़ रुपए का इनाम था। वह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रहने वाला था। अन्य नक्सलियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को छत्तीसगढ़-उड़ीसा सीमा पर एक संयुक्त अभियान के दौरान दो महिला नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और एक राइफल सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात फिर से गोलीबारी शुरू हुई जो मंगलवार की सुबह तक जारी रही जिसमें 12 और नक्सली मारे गए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में गरियाबंद जिला पुलिस इकाई के सुरक्षाकर्मियों का एक संयुक्त दल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कोबरा कमांडो और उड़ीसा पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के जवान शामिल थे। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से लगभग पांच किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुल्हाड़ीघाट आरक्षित वन में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर 19 जनवरी की रात को यह अभियान शुरू किया गया था। मारे गए 14 नक्सलियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर के डॉ. भीम राव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल लाया गया है।

इस मुठभेड़ के साथ ही इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 42 नक्सली मारे जा चुके हैं।

# वाहन प्रदर्शनी का समापन, 200 उत्पादों की पेशकश देखने आठ लाख लोग पहुंचे

**नई दिल्ली/भाषा**

वाहन उद्योग प्रदर्शनी 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025' बुधवार को संपन्न हो गई। इस प्रदर्शनी में करीब 200 उत्पादों की पेशकश की गयी। राष्ट्रीय राजधानी में 17 जनवरी से 22 जनवरी तक भारत मंडपम एवं यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में सम्मिलित रूप से आयोजित इस प्रदर्शनी में 1,500 से अधिक कंपनियों ने शिरकत की।आयोजकों ने कहा कि इस दौरान वाहन, कलपुर्जा एवं प्रौद्योगिकी खंडों में प्रदर्शित नए एवं मौजूदा उत्पादों को देखने के लिए आठ लाख से अधिक लोग पहुंचे।

इस आयोजन को मिले जोरदार समर्थन से उत्साहित सरकार अब इसे सालाना आयोजित करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। अभी तक इस प्रदर्शनी का आयोजन दो साल में एक बार होता है। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने एक्सपो के दौरान 200 से अधिक उत्पादों का अनावरण देखा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जनवरी को भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, एच डी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल एवं हरदीप सिंह पुरी के साथ वाहन क्षेत्र के दिग्गज कारोबारियों की मौजूदगी में एक्सपो का उद्घाटन किया था।

भारत मंडपम में आयोजित वाहन प्रदर्शनी के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) ने खूब सुर्खियां बटोरीं। यात्री वाहन बाजार की अग्रणी मारुति सुजुकी और हुंदै मोटर इंडिया ने अपने ईवी उत्पाद उतारकर इस नए वाहन खंड में भी बड़ी भूमिका निभाने की मंशा जता दी।

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन 'ई-विटारा' पेश किया जिसे भारत में बनाकर 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। वहीं

हुंदै मोटर इंडिया ने 'क्रेटा इलेक्ट्रिक' को पेश किया।

इसके अलावा वियतनाम की विनफास्ट और चीन की बीवाईडी ने भी यात्री वाहन खंड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, 2025 के दूसरे संस्करण ने परिवहन से जुड़ी पूरी मूल्य शृंखला को एक ही छत के नीचे लाने का काम किया। इनमें वाहन विनिर्माताओं से लेकर कलपुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, टायर एवं बैटरी भंडारण निर्माता और वाहन सॉफ्टवेयर फर्में भी शामिल हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाहन एवं परिवहन क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना था, जिसमें टिकाऊ और प्रौद्योगिकी प्रगति पर जोर दिया गया।

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि वाहन प्रदर्शनी में कंपनियों ने टिकाऊ परिवहन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने टिकाऊ परिवहन पर उद्योग के फोकस को प्रदर्शित किया। अग्रवाल ने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को वार्षिक आयोजन बनाने के लिए वाहन उद्योग और अन्य पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम इसका (वार्षिक) आयोजन पसंद करेंगे, लेकिन हम सभी के सुझावों और चर्चाओं के लिए खुले रहेंगे। दरअसल हम एक बड़ा मूल्य आधार तैयार करना चाहते हैं। अग्रवाल ने कहा कि इस आयोजन में बहुत अधिक मेहनत एवं धन खर्च होता है, लिहाजा स्पष्ट मूल्य प्रस्ताव की जरूरत है। ऐसी स्थिति में यह प्रतिबद्धता नहीं जताई जा सकती है कि यह सालाना या दो साल में एक बार होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि सरकार देश में अधिक वैश्विक आयोजन करने पर जोर दे रही है।

# पीएसी की बैठक में 'आसमान छूते हवाई किराये' का मुद्दा उठा, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग

नई दिल्ली/भाषा। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठक में बुधवार को आसमान छूते हवाई किराये और सरकारी एजेंसियों तथा नियामकों की ओर से पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने को लेकर चिंता जताई गयी तथा कई सांसदों ने यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए निजी हवाईअड्डा संचालकों और विमानन कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीएसी अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल ने समिति की इस बैठक को 'बेहतरीन बैठकों में से एक' बताया। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों ने चिंता जताई कि हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) नियामक के रूप में ठीक से काम नहीं कर रहा है।बैठक के बाद उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''हमें स्पष्ट जवाब चाहिए।''

उनका कहना था कि नियामक संस्था सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं दे सकी।

वरिष्ठ कांग्रेस सांसद ने कहा, ''सदस्यों ने चिंता जताई थी कि हवाई किराया आसमान छू रहा है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) या नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।''

सूत्रों ने बताया कि कुछ सांसदों ने उपयोगकर्ता विकास शुल्क में ''मनमाने ढंग से वृद्धि जैसे मुद्दों पर नाखुशी के बीच किराया को विनियमित करने के लिए एईआरए अधिनियम में संशोधन का आह्वान किया ताकि इस कानून को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

# पलानीस्वामी एवं अन्नाद्रमुक ने तमिलनाडु को राजस्व घाटे वाला प्रदेश बना दिया : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**शिवगंगा।** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी पर राज्य की राजकोषीय स्थिति की आलोचना करने के लिए निशाना साधा और कहा कि उनकी अन्नाद्रमुक की सरकार ने एक दशक पहले राज्य को राजस्व घाटे वाला प्रदेश बना दिया था। मुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद, सत्तारूढ़ द्रमुक विभिन्न कल्याणकारी पहलों को लागू करते हुए राज्य को विकास के पथ पर ले जा रही है। इससे एक दिन पहले पलानीस्वामी ने राज्य की राजकोषीय स्थिति को लेकर सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार पर निशाना साधा और दावा किया था कि तमिलनाडु का बढ़ता कर्ज एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात सत्तारूढ़ पार्टी की उपलब्धि प्रतीत होता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि चार साल पहले द्रमुक के सत्ता में आने के बाद से तमिलनाडु सबसे अधिक कर्ज वाला राज्य बन गया है, जबकि द्रमुक ने राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आश्वासन दिया था। इस पर पलटवार करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु 2011 में एक राजस्व-अधिशेष राज्य था। द्रमुक के सत्ता से हटने के बाद अन्नाद्रमुक ने एक दशक तक प्रदेश पर शासन किया था। उन्होंने कहा, यह अन्नाद्रमुक की सरकार थी जिसने तमिलनाडु को 2013 में राजस्व घाटे वाला राज्य बना दिया, जबकि प्रदेश 2011 में राजस्व अधिशेष वाला राज्य था। उन्होंने 2017-19 के दौरान तमिलनाडु को सबसे अधिक राजस्व घाटे वाले राज्य के रूप में संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया और हमने प्रदेश को इस विकट स्थिति से बचाया है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र तमिलनाडु को धन आवंटन करने के मामले में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी चुनौतियों के बावजूद राज्य अच्छी प्रगति कर रहा है।

# द्रमुक सांसद राजा ने वक्फ समिति की बैठकें स्थगित करने का आग्रह किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली।** द्रमुक सांसद ए. राजा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति के प्रमुख जगदंबिका पाल को बुधवार को पत्र लिखकर आग्रह किया कि 24 और 25 जनवरी को समिति की प्रस्तावित बैठक स्थगित की जाए।

जगदंबिका पाल को लिखे पत्र में राजा ने कहा कि सदस्यों के लिए इतने कम समय के नोटिस पर वक्फ विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव देने और चर्चा के लिए आवश्यक साक्ष्य एवं सामग्री को जमा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि मंगलवार को लखनऊ में विभिन्न हितधारकों से मिलने के कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने पाल से विधेयक पर खंड दर खंड विचार करने के लिए 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था। यह समिति पिछले साल अगस्त में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए जाने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही है। राजा ने कहा कि यदि जेपीसी की ये बैठकें स्थगित नहीं की जातीं हैं, तो जेपीसी के गठन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा क्योंकि इससे भारत के लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाएगा कि प्रस्तावना में निहित संविधान का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना खतरे में है और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

राजा ने कहा, इसलिए, विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से प्रार्थना की जाती है कि 24 और 25 तारीख को प्रस्तावित जेपीसी की बैठक को इस महीने की 30 और 31 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, जैसा कि आपके साथ लखनऊ में पहले ही चर्चा हो चुकी है।

कांग्रेस ने अपने 'एक्स' हैंडल पर राजा का यह पत्र साझा करते हुए पोस्ट किया, लोकसभा सदस्य और वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य ए राजा द्वारा विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर जेपीसी की बैठकों को 24 और 25 जनवरी से 30 और 31 जनवरी 2025 तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

पाल को लिखे गए पत्र में राजा ने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने 20 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से समिति के सदस्यों से बुधवार शाम चार बजे तक प्रस्तावित विधेयक में अपने संशोधन भेजने का अनुरोध किया है। यह भी बताया गया है कि विधेयक पर खंड-दर-खंड विचार के लिए जेपीसी की अगली बैठक 24 और 25 जनवरी को भी बुलाई गई है। द्रमुक सांसद ने कहा कि यह बहुत अजीब है कि जेपीसी की बैठक की अगली तारीखों की घोषणा बिना किसी औपचारिक चर्चा के जल्दबाजी में की गई, जबकि जेपीसी पहले से ही दौरे पर थी।

# श्रीलंका ने 41 भारतीय मछुआरों को स्वदेश भेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**कोलंबो।** श्रीलंका नौसेना द्वारा हिरासत में लिये गये 41 भारतीय मछुआरों को यहां के अधिकारियों ने स्वदेश वापस भेज दिया है। भारतीय मिशन ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दोनों देशों के मछुआरों को अनजाने में एक-दूसरे के जलक्षेत्र में घुसने के कारण अक्सर गिरफ्तार किया जाता है।

भारतीय उच्चायोग ने यहां 'एक्स' पर कहा, 41 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से सफलतापूर्वक वापस लाया गया! वे अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गये हैं।

मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसमें श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों ने पाक जलडमरूमध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी भी की है और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से घुसने की कई कथित घटनाओं में उनकी नौकाओं को जब्त किया है। पाक जलडमरूमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है।

# निर्वाचन आयोग ने इरोड पूर्व के निर्वाचन अधिकारी का तबादला किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**इरोड।** निर्वाचन आयोग ने इरोड पूर्व विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी (आरओ) एन मनीष का तबादला कर दिया है और उनकी जगह एच. एस. श्रीकांत को इरोड सिटी नगर निगम का आयुक्त और इस निर्वाचन क्षेत्र का नया आरओ नियुक्त किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह आदेश मंगलवार देर रात जारी किया गया। श्रीकांत ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया और अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों का समन्वय शुरू कर दिया। इरोड सिटी नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों से 17 जनवरी तक नामांकन पत्र स्वीकार किये गये थे। उम्मीदवारों में से एक पद्मावती मंजूनाथ स्वामी निलयम, उदयनगर, बेंगलूरु की निवासी हैं तथा उनका नाम कर्नाटक के कृष्णराजपुरम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है।

उनका नामांकन 17 जनवरी को आरओ को प्रस्तुत किया गया था। जांच के बाद, उनके नामांकन को शुरू में स्वीकार कर लिया गया था। बीस जनवरी को अपराह्न तीन बजे आरओ ने पद्मावती समेत 47 उम्मीदवारों की अंतिम सूची मीडिया के सामने घोषित की। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि, तीन निर्दलीय उम्मीदवारों- पद्मराजन, अजवार और नूर मोहम्मद ने पद्मावती का नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दलील दी कि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, केवल तमिलनाडु में रहने वाले और राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति ही राज्य में चुनाव लड़ने के पात्र हैं। जांच के बाद अधिकारियों ने माना कि पद्मावती का नामांकन स्वीकार करना एक गलती थी। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी राजा गोपाल सुंकारा ने जांच की और तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। असमंजस की स्थिति के कारण उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा में देरी हुई। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद पद्मावती का नामांकन खारिज कर दिया गया और 46 उम्मीदवारों की संशोधित अंतिम सूची जारी की गई। इरोड पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक ई वी के एस इलनगोवन के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराये जाने की आवश्यकता पड़ी। मतदान पांच फरवरी को होगा।

# केरल सरकार पर कर्मियों के लाभ रोकने का आरोप, मंत्री ने दावे को खारिज किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**तिरुवनंतपुरम/भाषा।** कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने बुधवार को केरल सरकार पर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले विभिन्न सेवा लाभों का भुगतान न करने का आरोप लगाया।

वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि देश में यह वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति सबसे अधिक दयालु है। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए यूडीएफ ने आरोप लगाया कि वाम मोर्चा सरकार पर सरकारी कर्मचारियों का एक लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसने दावा किया कि इतनी बड़ी रकम रोके रखने के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति खराब बनी हुई है। यूडीएफ नेताओं ने शून्यकाल के दौरान इस 'गंभीर मुद्दे' को चर्चा के लिए नहीं उठाए जाने पर विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष ने यह मुद्दा उसी दिन उठाया जब सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग वेतन संशोधन, महंगाई भत्ते के बकाए के भुगतान और अन्य मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन कर रहा है।

कर्मचारियों की इस हड़ताल को विपक्षी दलों से संबद्ध श्रमिक संगठनों के साथ-साथ एलडीएफ के घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का भी समर्थन प्राप्त है। स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस स्वीकार करने की मांग करते हुए कांग्रेस के पी सी विष्णुनाथ ने सरकार से सरकारी कर्मियों की मांगों का सहानुभूति के साथ समाधान करने की अपील की। उन्होंने अनुरोध किया कि कर्मियों के बारे में ऐसा नहीं समझा जाए कि वे संभ्रात वर्ग से हैं।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी सार्वजनिक रूप से एक सक्षम प्रशासक के रूप में उनकी प्रशंसा करते हैं, वे ही गुप्त रूप से उनके शासन में अपने पात्र योग्य सेवा लाभों से वंचित होने पर विलाप कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने वाम सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता, अवकाश नकदीकरण और वेतन संशोधन के लिए कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि क्रमशः 35,000 करोड़ रुपये, 24,500 करोड़ रुपये और 5,500 करोड़ रुपये है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि केरल के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतने बड़े भुगतान में कभी चूक नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि विजयन सरकार के 103 महीने के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों को पिछले छह महीनों से उनके लाभ नहीं मिले हैं।

हालांकि, मंत्री बालगोपाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश में कोई भी अन्य राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के साथ केरल की तरह दयालुता से पेश नहीं आती है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के आरोपों में बिलकुल भी तथ्य नहीं हैं।

# माकपा की केरल इकाई के सचिव के बयान पर मुस्लिम मौलाना ने नाराजगी जताई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**तिरुवनंतपुरम।** मुस्लिम मौलाना और जेम-इय्यातुल उलेमा के महासचिव एपी अबूबाकर मुस्लियार ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरुषों के व्यायाम सत्रों पर अपने बयान की आलोचना करने के लिए माकपा की केरल इकाई के सचिव एमवी गोविंदन पर निशाना साधा है।

उन्होंने मंगलवार को कहा, जब हम अपने धर्म को लेकर कुछ कहते हैं तो माकपा सचिव को हमारा अपमान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमने दूसरे धर्मों के बारे में कुछ नहीं कहा है।

मौलाना मुस्लियार ने पुरुषों के प्रभुत्व के खिलाफ गोविंदन के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि माकपा नेता के गृह जिले कन्नूर में उनकी पार्टी द्वारा चुने गए 18 क्षेत्रीय सचिवों में एक भी महिला क्यों नहीं है। उन्होंने पूछा, उनकी पार्टी में महिलाओं को महत्व क्यों नहीं दिया जाता। मौलाना मुस्लियार ने रविवार को अपने भाषण में कहा था कि महिलाओं और पुरुषों के व्यायाम सत्र इस्लामी विचारधारों के खिलाफ हैं और इन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वह राज्य में खासतौर पर उत्तरी जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित हो रहे व्यायाम सत्रों का जिक्र कर रहे थे। गोविंदन ने बाद में पक्कलड़ में अपने भाषण में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की मौजूदगी का विरोध करने के लिए कुछ लोगों की आलोचना की।

# कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस शोषण को रोकने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम : जी. परमेश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तुमकुर । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को तुमकुर में कहा कि राज्य में माइक्रोफाइनेंस शोषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने आश्वासन दिया है कि पुलिस ने पहले से ही माइक्रोफाइनेंस शोषण और उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। तुमकुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुमकुरु जिले में ऐसी कोई उत्पीड़न की घटना सामने आती है, तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि तिपटूर में एक महिला की आत्महत्या के संबंध में, दोषियों के खिलाफ कदम उठाए जा चुके हैं।

जी. परमेश्वर ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में अपनी समझ साझा की और सेवा और त्याग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई कांग्रेस सदस्यों ने अपनी संपत्तियां कुर्बान कर दी थीं और कई बलिदान भी दिए गए। हालांकि, आज के समाज में त्याग की ऐसी भावना कम हो गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने शिवकुमार स्वामी के योगदान पर भी प्रकाश डाला, जिन्होंने देश में समाज सेवा के एक नए रूप का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि वे भविष्य के लिए बेहतर नागरिकों के निर्माण के लिए भोजन और शिक्षा दान के आदर्शों को जोड़ने में विश्वास करते थे। वे अच्छे नागरिकों को तैयार करने के लिए कम उम्र से ही संस्कृति, परंपरा और धर्म सिखाने के महत्व पर जोर देते थे। उनकी अनूठी सेवा याद रखने लायक है।

दसोहा (दूसरों की सेवा) के दिन के बारे में मंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेगी। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद शिवकुमार स्वामी की जन्मस्थली पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए आगामी बजट में धन आवंटित करने की योजना का भी जिक्र किया।

# दो अलग-अलग सड़क हादसों में 14 लोगों की मौत

येल्लापुरा/रायचूर। उत्तर कन्नड़ और रायचूर जिलों में बुधवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में 14 लोगों की मौत हो गयी और 24 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन वह उपचाराधीन है। हादसों पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने कहा कि मृतकों के परिवारों को उचित अनुग्रह राशि दी जाएगी। सिद्दरामय्या ने एक बयान में कहा, उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर और रायचूर जिले के सिंधनूर में दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत की खबर हृदय विदारक है। मैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

उन्होंने कहा, मृतकों के परिवारों को सरकार द्वारा उचित अनुग्रह राशि दी जाएगी। पुलिस ने बताया कि येल्लापुर में 29 फल विक्रेताओं को ले जा रहा एक ट्रक बुधवार सुबह सावनूर-हुबली रोड पर वन क्षेत्र में 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एम नारायण ने बताया कि हावेरी जिले के सावनूर के निवासी पीड़ित फल बेचने के लिए येल्लापुर मेले जा रहे थे।

# इसरो ने गगनयान के पहले मानवरहित मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल भेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**बेंगलूरु।** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी) ने द्रव प्रणोदन प्रणाली के एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गगनयान के पहले मानवरहित मिशन के वास्ते क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष की कक्षा के लिए रवाना किया है। इसरो ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गगनयान अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की क्षमता हासिल करने की दिशा में इसरो का पहला प्रयास है। इसरो गगनयान परियोजना के तहत मानवयुक्त चालक दल को रवाना करने से पहले अंतरिक्ष में एक मानवरहित मिशन भेजने की योजना बना रहा है। इसरो ने एक बयान में कहा, 21 जनवरी 2025 को इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी) ने द्रव प्रणोदन प्रणाली के एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गगनयान के पहले मानवरहित मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष रवाना किया। क्रू मॉड्यूल एक पूर्ण स्वायत्त अंतरिक्ष यान है, जिसे तीन सदस्यीय चालक दल को अंतरिक्ष की कक्षा में ले जाने और मिशन अवधि पूरी होने के बाद धरती पर सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलूरु स्थित एलपीएससी ने क्रू मॉड्यूल को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया।

इसरो के मुताबिक, क्रू मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली (सीएमपीएस) एक द्वि-प्रणोदक आधारित प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली (आरसीएस) है, जिसे क्रू मॉड्यूल को सटीक 3-अक्ष नियंत्रण (पिच, यॉ और रोल) प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, इस प्रणाली में 12 100एन थ्रस्टर, उच्च दबाव वाली गैस बोतलों के साथ दबाव प्रणाली और संबंधित द्रव नियंत्रण घटकों के साथ प्रणोदक प्रवाह प्रणाली शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, 100एन थ्रस्टर रॉकेट मोटर हैं, जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान में प्रणोदन के लिए किया जाता है।

उन्होंने बताया कि एलपीएससी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा डिजाइन किए गए क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम (सीएमयूएस) को भी मॉड्यूल में एकीकृत किया है। इसरो के मुताबिक, क्रू मॉड्यूल को कक्षीय मॉड्यूल के एकीकरण के अंतिम चरण के लिए बेंगलूरु स्थित यूआर राव उपग्रह केंद्र भेजे जाने से पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एवियोनिक्स और विद्युत दोहन प्रणालियों की असेंबली एवं परीक्षण सहित अन्य एकीकरण प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

## प्रदर्शन

दलित हक्कुगाला समिति के सदस्यों ने बुधवार को राज्य बजट में एससीएसटी के लिए विशेष पैकेज की मांग को लेकर बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया।

# युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती लत गंभीर चिंता का विषय : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं विशेषकर स्कूल, कॉलेज के छात्रों में नशाखोरी की बढ़ती लत पर चिंता जताते हुए इसे पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार एवं

समाज दोनों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि पूरे देश में नशे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आमतौर पर कॉलेज में जाने पर बच्चों का नशे के प्रति रुझान दिखता था, लेकिन अब स्कूल भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों से बात करने पर पता चलता है कि 10वीं, 12वीं के बच्चे भी शराब और नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। ऐसी बातें सामने आई हैं कि बच्चे हर छोटे-बड़े आयोजन में शराब का सेवन करते हैं, जो पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।उन्होंने कहा कि नशे के बढ़ते खेल के पीछे वजह प्रशासन और सरकार का इस ओर बेहद गंभीर नहीं होना, पुलिस की इस व्यापार में शामिल लोगों के साथ संलिप्तता तथा अभिभावकों के पास बच्चों के लिए पर्याप्त समय नहीं होना है। गहलोत के अनुसार, राजस्थान की ही बात करें तो पांच साल में 50 से अधिक पुलिसकर्मी नशे के कारोबार में शामिल पाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मादक पदार्थ पर प्रतिबंध के कानून हैं एवं सजा का भी प्रावधान है, लेकिन मुकदमे का लंबा समय, सबूतों का अभाव जैसी वजहों से आरोपी छूट जाते हैं। 'एमडीएमए टैबलेट' जैसी नशे की गोलियां बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं जिससे युवा इसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं और हमारी नयी पीढ़ी बर्बाद हो रही है।

उन्होंने कहा, हम सभी को सरकार एवं समाज दोनों के तौर पर ये सोचना होगा कि क्या पैसा कमाना, स्वयं के लिए सुख-सुविधाएं जुटाते रहना या अन्य प्राथमिकताएं हमारे बच्चों के भविष्य से अधिक जरूरी हैं? क्या इसको लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई हम नहीं कर सकते? राजस्थान के हालात का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, वैसे तो ये समस्या पूरे प्रदेश में ही फैलती जा रही है लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर में तस्कर गिरोह सक्रिय रूप से नशे का कारोबार चला रहे हैं।

# सबका साथ, सबका विकास हमारा लक्ष्य : भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक सशक्त और समृद्ध समाज के निर्माण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच की अहम भूमिका है। इनका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव होता है तथा वे राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजट में प्रत्येक वर्ग की जरूरतों का समावेश कर सभी के सुझावों को यथासंभव समाहित करेगी जिससे सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को गति मिले।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी एवं उपभोक्ता मंच जैसे संगठन अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तथा इनके अनुभव का लाभ जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय की अवधारणा पर काम कर रही है जिसके तहत अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले तथा वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके।

शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास राज्य की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के 20 करोड़ मानव दिवस को बढ़ाकर 27 करोड़ मानव दिवस किया गया है। अब तक 24 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। साथ ही, योजना के तहत लगभग सभी श्रमिकों का भुगतान 15 दिन में किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। राजीविका के तहत राज्य में 20 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है तथा लखपति दीदी योजना के तहत 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री में सहयोग भी दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 55 हजार से ज्यादा आवासों को स्वीकृति दी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत बारां जिले में सहरिया जनजाति के लिए विशेष अभियान चलाकर 17 हजार से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों ने स्वरोजगार केन्द्र स्थापित करने, नशा मुक्ति केन्द्र खोलने, सिलिकोसिस बीमारी से रोकथाम, गांवों तक योजनाओं का प्रचार-प्रसार, बाल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, घुमन्तू वर्गों को संबल, बालश्रम की रोकथाम हेतु कार्यवाही, स्वयं सहायता समूह, दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, जेण्डर बजट, रिसर्च सेंटर फॉर कन्ज्यूमर केयर, प्रवासी श्रमिक बोर्ड का गठन, विमंदितों के लिए पुनर्वास गृह सहित विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखी। बैठक में अपना घर आश्रम, उमंग, सेवा भारती, नया सवेरा, भगवान महावीर चाइल्ड केयर, अलख फाउंडेशन, प्रयास संस्थान, सेव द चिल्ड्रन, अक्षय पात्र फाउंडेशन, घुमन्तू जाति उत्थान न्यास सहित विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

# प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण सजगता के साथ होगा : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में आगामी 2 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फरवरी माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री निवास पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपादित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण सजगता एवं सतर्कता के साथ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र संग्रहण और वितरण पर विशेष सतर्कता बरती जाए। जिला प्रशासन, पुलिस एवं आरपीएससी परस्पर समन्वय कर बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ परीक्षा संपादित करें। उन्होंने कहा कि प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग ना हो इसके लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर और एसपी फरियादी की फरियाद संवेदनशीलता के साथ सुनें एवं उनका त्वरित निस्तारण करें। जनता की समस्या के निदान में लापरवाही और देरी करने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिये भी निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने जिला कलक्टर्स को महत्वपूर्ण कार्यों की नियमित समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया।

शर्मा ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहे और डिबार किये गए परीक्षार्थियों पर निगरानी करने लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के निकट क्षेत्रों का सघन निरीक्षण भी किया जाए। स्थानीय पुलिस थाना विशेष सतर्कता के साथ कार्य करें। बैठक में आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए आवेदन पत्र और अटेंडेस शीट पर थंब इम्प्रेशन लेने का नवाचार भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा से दो दिन पूर्व एवं पश्चात निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जा रही है। परीक्षार्थियों को सुलभ यातायात के लिए परिवहन विभाग बसों की समय सारणी भी जारी करे। शर्मा ने कहा कि परीक्षा प्रबंधन में लगे कार्मिकों का समयबद्ध प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी निर्देशित किया। शर्मा ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फरवरी माह में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27-28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने एग्रीस्टैक योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री रोल-आउट पर अधिकारियों को मिशन मोड़ पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अवगत कराया गया कि आगामी 5 फरवरी से चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैम्प लगाए जाएंगे। बैठक में प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर आधारित पंच-गौरव कार्यक्रम के संबंध में गाइडलाइन के बारे में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि, मंगला पशु बीमा योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।

## पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकली दलित दूल्हे की बारात

जयपुर। राजस्थान के अजमेर जिले में दलित समाज के एक दूल्हे की बारात पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच निकली क्योंकि दुल्हन के परिवार को आशंका थी कि गांव के उच्च जाति के लोग इसमें बाधा डाल सकते हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। मामला 21 जनवरी को जिले के लवेरा गांव का है जहां युवती अरुणा खोरवाल के परिवार के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से संपर्क कर बारात व बारातियों की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई। प्रशासन ने बारात आदि की सुरक्षा के लिए लगभग 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। दूल्हा विजय रेगर घोड़ी पर बैठकर दुल्हन के घर पहुंचा जिसके बाद पारंपरिक 'बिंदोली' की रस्म निभाई गई।

अजमेर की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कहा, एक परिवार ने पुलिस के सामने चिंता जताई थी कि वे बारात निकालना चाहते हैं और इसमें कुछ परेशानी हो सकती है। एहतियातन गांव में बैठक की गई और ग्रामीणों ने भी समर्थन दिया था कि कोई समस्या नहीं होगी। बारात, पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। अरुणा के पिता नारायण खोरवाल ने भी स्थानीय कार्यकर्ताओं से मदद मांगी थी।

खोरवाल ने कहा, अगर हम डरे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम एक शिक्षित परिवार हैं। पहले भी बारात निकलने के दौरान अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए हमने पुलिस और कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस के सहयोग से शादी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। खोरवाल ने कहा कि उन्होंने बारात निकासी के लिए मानव विकास एवं अधिकार केंद्र संस्थान के सचिव रमेश चंद बंसल से मदद मांगी थी।

# राज्य सरकार विशेष योग्यजनों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध : अविनाश गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के पुनर्वास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। गहलोत ने बुधवार को अंबेडकर भवन के सभागार में राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने विशेष योग्यजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग को पंचायत समिति, जिला स्तर पर कैंप लगाकर कम से कम समय में यूडीआईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्माणाधीन राजकीय भवनों, गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को विशेष योग्यजन के लिए सुगम्य और बाधारहित बनाने के भी निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सीएसआर फंड के माध्यम से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जिला स्तर की औद्योगिक इकाइयों को प्रपोजल भेजने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को योग्यजनों के कल्याण के कार्यों में लगाया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका ने बैठक में आए संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव विशेष योग्यजन एच गुईटे ने सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित आंकड़ों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही न्यूमोकोनियोसिस नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को भी साझा किया। बैठक में सिलिकोसिस योजना की मॉनिटरिंग और पुनर्वास, स्वावलम्बन पोर्टल पर यूडीआईडी या दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण के संबंध में चिकित्सा विभाग से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सुगम्य भारत अभियान में जिलों से प्रस्ताव मंगवाने और विशेष योग्यजन विभाग के जिला कार्यालय बनाये जाने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में विशेष योग्यजनों के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारक विभागों से समन्वय स्थापित किये जाने की भी चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सा, शहरी विकास, स्कूल शिक्षा, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, साक्षरता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डीओपी, पंचायतीराज, श्रम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं प्रदेश भर की प्रमुख गैर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

# डेल्फिक ने स्कूली बच्चों को करवाया कला-शिल्प से रूबरू

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती वीनू गुप्ता ने बुधवार को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और एमजीडी गर्ल्स स्कूल डेल्फिक क्लब द्वारा एमजीडी प्रांगण में आयोजित क्राफ्ट डेमोंस्ट्रेशन, फॉरगॉटन स्टोरीज का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम सैंकड़ों स्कूली छात्राओं को राजस्थानी संस्कृति और कला से रूबरू करवाने का माध्यम बना। प्रदर्शनी में विख्यात शिल्पकारों ने छात्राओं के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन किया। विभिन्न शिल्पकलाओं के माध्यम से राजस्थान के बेहतरीन शिल्प-समृद्ध इतिहास को दर्शाया गया।

कार्यक्रम में राज्य पुरस्कार विजेता सुनील प्रजापति द्वारा राजस्थान की सुप्रसिद्ध मूर्तिकला का, राजेश भट्ट एवं परिवार द्वारा कठपुतली कला, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार रामस्वरूप जांगिड़ द्वारा तारकशी कला का प्रदर्शन किया गया। छात्राओं ने मूर्ति निर्माण कला, कठपुतली बनाने और इसे अपने हाथों की उँगलियों पर नचाने की कला के साथ साथ तारकशी कला को भी करीब से जाना। इसी प्रकार वरिष्ठ कैलीग्राफी मास्टर हरिशंकर बालोठिया की कैलीग्राफी की कला में छात्राओं की विशेष रूचि देखने को मिली। सुन्दर और कलात्मक लेखन से संबंधित इस कला को अपने अध्ययन में उपयोग में लेने की रूचि छात्राओं ने जाहिर की। श्रीमती वीनू गुप्ता ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना मनकोटिया भी उनके साथ रही।

# अश्लील हरकतों पर शिक्षा मंत्री की सख्त चेतावनी : बेटा-बेटी भूखे मरेंगे, बर्खास्त होंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चित्तौड़गढ़। जिले के सरकारी स्कूल में हेड मास्टर और महिला टीचर के अश्लील वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा रुख अपनाया है। दिलावर ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा के मंदिर को इस तरह अपवित्र करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, वे अपनी आदतों से बाज आएं, अन्यथा उनके बेटा-बेटी और खुद भी भूखे मरेंगे।

चित्तौड़गढ़ के एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर और महिला टीचर के अश्लील हरकतों वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया। साथ ही विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जांच शुरू हो गई है।शिक्षा विभाग ने एक जांच कमेटी गठित की। जांच

के दौरान महिला टीचर ने वीडियो में खुद के होने की बात मानी लेकिन इसे एडिट बताया। वहीं, हेड मास्टर ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और जांच टीम के सामने पेश भी नहीं हुए। कमेटी ने वीडियो को प्रमाणिक पाया और इसे विभाग की छवि के लिए अक्षम्य अपराध करार दिया। शिक्षा मंत्री ने मीडिया को बताया, स्कूलों को शिक्षा और संस्कार का मंदिर माना जाता है। अगर कोई यहां इस तरह की अश्लील हरकत करता है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

# जयपुर में 14 लाख रुपये का मादक पदार्थ जब्त

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को जयपुर में छापेमारी कर 14 लाख रुपये मूल्य की नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किये। एनसीबी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एनसीबी ने एक बयान में कहा कि उसे मानस पोर्टल पर एक शिकायत मिली, जिसके बाद रणनीतिक जानकारी एकत्र की गई और नवल विहार में अग्रवाल मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर छापा मारा गया। एनसीबी के जोनल निदेशक घनश्याम सोनी ने बताया कि छापेमारी में 3,552 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए गए, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत 14.20 लाख रुपये है। एनसीबी की टीम ने इस सिलसिले में नवल किशोर कुमावत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।

## नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

जयपुर। राजस्थान के जालौर जिले की एक अदालत ने पांच महीने पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रही पोक्सो अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी भगाराम उर्फ भगवत कुमार को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

## न्यायपालिका तक पहुंच को हथियार बनाया जा रहा है, व्हिप से लगता है स्वतंत्रता पर अंकुश : धनखड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका तक पहुंच को 'हथियार' बनाया जा रहा है और यह भारत के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। धनखड़ ने यह भी कहा कि संस्थाएं अपने अधिकार क्षेत्र में काम नहीं कर रही हैं। उनका यह भी कहना था कि संसद में जनप्रतिनिधियों पर व्हिप लगाना उनकी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करना है। उन्होंने कहा, ''हर दिन आप देखते हैं कि सलाहें जारी की जा रही हैं, कार्यकारी कार्य ऐसे निकायों द्वारा किए जा रहे हैं जिनके पास उन्हें करने का कोई अधिकार क्षेत्र या न्यायिक अधिकार अथवा क्षमता नहीं है। उनका इशारा न्यायपालिका की ओर था। उन्होंने कहा, ''इसे आम आदमी की भाषा में कहें तो, एक तहसीलदार कभी प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता...।''

उपराष्ट्रपति ने यहां 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप' के छात्रों को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा, ''देश में हमारे पास एक मौलिक अधिकार है, और अधिकार यह है कि हम न्यायपालिका तक पहुंच सकते हैं। यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में न्यायपालिका तक पहुंच को हथियार बना लिया गया है... यह हमारे शासन, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है।''

धनखड़ का मानना है कि संस्थाएं अन्य संस्थाओं के सामने झुक रही हैं, ''और ऐसा सुविधा के लिए किया जा रहा है''। उन्होंने कहा, ''खुश करने के ये तरीके अल्पकालिक लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये संस्थानों के आंतरिक तंत्र को ऐसी क्षति पहुंचा सकते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।''

## अखिलेश ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक को लेकर आलोचना की, इसे सियासी कदम करार दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**लखनऊ/भाषा।** समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कुंभ मेला क्षेत्र में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की आलोचना की और इसे संदेश देने के लिए उठाया गया एक राजनीतिक कदम बताया।

उनकी यह प्रतिक्रिया मेला परिसर में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रियों द्वारा त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के तुरंत बाद आई।

यादव ने दिवंगत समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ''कुंभ और प्रयागराज राजनीति या राजनीतिक कार्यक्रमों की जगह नहीं है। वहां आयोजित पूरी कैबिनेट बैठक राजनीतिक है जिसका उद्देश्य राजनीतिक संदेश देना है।''

यादव ने संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बारे में पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, ''समाजवादी पार्टी के सदस्यों को अपनी माताओं और गंगा में गहरी आस्था है। हममें से कई लोग बिना किसी प्रचार या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा किए पहले ही डुबकी लगा चुके हैं।'' कार्यक्रम के दौरान यादव ने जनेश्वर मिश्र को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें 'सादगी का प्रतीक व्यक्ति' तथा समाजवादी आंदोलन के एक दिग्गज नेता के रूप में वर्णित किया। यादव ने कहा, ''मिश्र जी ने अपना जीवन समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें 'छोटे लोहिया' के नाम से जाना जाता था। उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि समाजवादी उनके दिखाए रास्ते पर चलें।''

## जद (यू) ने पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को हटाया, भाजपा सरकार को समर्थन जारी रहेगा

**नई दिल्ली/इम्फाल/भाषा।** जनता दल (यूनाईटेड) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अपने संबंधों को लेकर बढ़ती अटकलों को शांत करने के प्रयास में बुधवार को अपनी मणिपुर इकाई के अध्यक्ष के. बीरेन सिंह को बर्खास्त कर दिया।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अनुशासनहीनता के कारण सिंह को पद से हटा दिया गया है और पूर्वोत्तर के इस राज्य में भाजपा नीत सरकार का समर्थन जारी रहेगा। सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को एक पत्र लिखकर बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने के फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने पत्र में यह भी कहा था कि पार्टी के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर अब विपक्षी खेमे में बैठेंगे।

राज्यपाल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, ''फरवरी/मार्च 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में जद(यू) के छह उम्मीदवार फिर से जीते थे, जिनमें से पांच विधायक कुछ ही माह बाद भाजपा में शामिल हो गये थे। इन पांच विधायकों के खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के अधिकरण में लंबित है।'' जद (यू), भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा है।

## संभल में शाही जामा मस्जिद के पास मिले प्राचीन कुएं की खोदाई शुरू

**संभल (उप्र)/भाषा।** संभल प्रशासन ने बुधवार को कोट गर्वी इलाके में शाही जामा मस्जिद के पास मौजूद उस प्राचीन कुएं की खोदाई शुरू की जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने की शिकायत मिली थी। विवादित शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर क्षेत्र से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित यह कुआं क्षेत्र के 19 प्राचीन कुओं में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस कुएं का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है।

स्थानीय निवासी संजय कुमार ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, यह कुआं हरिहर मंदिर के पास स्थित है। यह एक पूजा स्थल हुआ करता था, जहां लोग बच्चे के जन्म या शादी जैसे शुभ अवसरों पर आते थे। कालांतर में इसे ढक दिया गया और इसका मूल स्वरूप बदल दिया गया। खोदाई से इसका ऐतिहासिक स्वरूप फिर से बहाल होगा। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिरीष चंद्र ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा कुएं को अवैध रूप से ढकने की शिकायत के बाद खोदाई शुरू की गई थी। उन्होंने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि कुएं पर अतिक्रमण करके उसे ढक दिया गया था। हम इसे बहाल करने के लिए खोदाई कर रहे हैं और आगे की जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

## शराब पर प्रस्तावित प्रतिबंध पूरे प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में एक कदम है: उमा भारती

**भोपाल/भाषा।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बुधवार को धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध के मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि यह पूरे राज्य में शराबबंदी की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकार ''धार्मिक शहरों'' में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है ताकि इन स्थानों की पवित्रता को बनाए रखा जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री भारती पिछले कुछ वर्षों से भाजपा शासित राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करती रही हैं। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में यादव को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ''मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा धार्मिक शहरों में पूर्ण शराब बंदी अभूतपूर्व निर्णय है।'' उन्होंने कहा, ''दो साल पहले हमारी सरकार द्वारा घोषित की गई शराब प्रतिबंध नीति बहुत ही जनहितकारी एवं व्यवहारिक थी। हम पूर्ण शराबबंदी की ओर ही बढ़ रहे थे। यह पूर्ण शराबबंदी की दिशा में एक और कदम है।''

## चिकित्सक बलात्कार-हत्याकांड: सीबीआई उच्च न्यायालय से संजय रॉय के लिए मृत्युदंड का अनुरोध करेगी

**नई दिल्ली/भाषा।** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आर जी कर बलात्कार एवं हत्या मामले में उच्च न्यायालय सेसंजय रॉय को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सियालदह की एक अधीनस्थ अदालत ने आर जी कर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में बलात्कार के बाद एक महिला चिकित्सक की हत्या के मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को कानूनी सलाह मिली है कि इस मामले को ''दुर्लभतम'' श्रेणी में रखा जा सकता है और दोषी के लिए मृत्युदंड उचित है। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा यथाशीघ्र सियालदह अदालत के आदेश के खिलाफ विस्तृत दलीलों के साथ अपील दायर किए जाने और दोषी को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किए जाने की संभावना है।

## शिकारियों की बिछाई बिजली की तारों की चपेट में आकर दंपत्ति की मौत

**कोरापुट/भाषा।** ओडिशा के कोरापुट जिले के एक जंगल में एक दंपत्ति की बिजली के तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। ये तारें कथित तौर पर शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों को फँसाने के लिए बिछाई गई थी। पुलिस ने बताया कि बलराम गलेल और उनकी पत्नी बाला सड़क किनारे चाय की दुकान चलाते थे और सोमवार की शाम नंदापुर थाना क्षेत्र के जंगल में जलावन के लिए लकड़ी लेने गए थे। जब वे घर नहीं लौटे तो उनके परिवार और पड़ोसियों ने उनकी तलाश शुरू की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया,''तलाश के दौरान उनके शव जंगल में बिजली के तारों में उलझे हुए पाए गए। यह तार संभवत: शिकारियों द्वारा जानवरों को फँसाने के लिए बिछाए गए थे।''

## ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 29 गिरफ्तार

**गोरखपुर (उप्र)/भाषा।** गोरखपुर शहर में एक अपार्टमेंट परिसर में चल रहे ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि शहर में मेडिकल कॉलेज रोड के पास स्थित जेमिनी पैराडाइज अपार्टमेंट परिसर में चल रहे एक ऑनलाइन सट्टा रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।

उन्होंने बताया कि मऊ पुलिस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रविवार को छापेमारी कर 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह पिछले छह महीनों से अपार्टमेंट परिसर में किराए के चार फ्लैट से फर्जी ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल चला रहा था। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 लैपटॉप, 100 स्मार्टफोन और 150 सिम कार्ड जब्त किए। संदिग्धों में से अधिकांश बिहार और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उन्हें कथित तौर पर 18 हजार से 22 हजार रुपए के बीच मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया था और वे आठ घंटे की शिफ्ट में काम करते थे। पुलिस ने बताया कि वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई ने मऊ निवासी के खाते में 34 लाख रुपए के संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने के बाद यह गिरोह प्रकाश में आया।

## केंद्रीय मंत्री खडसे ने लोगों से स्वतंत्रता संग्राम के तीर्थाटन के लिए अंडमान यात्रा की अपील की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**पोर्ट ब्लेयर/भाषा।** केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने बुधवार को लोगों से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह यात्रा स्वतंत्रता संग्राम के प्रति तीर्थयात्रा होगी।

खडसे ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई यातनाओं का गवाह रही सेलुलर जेल के अलावा इस द्वीपसमूह को 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद कराया था। वह बृहस्पतिवार को बोस की जयंती मनाने के लिए 'जय हिंद पदयात्रा' के तहत यहां पहुंचे थे। अधिकारियों ने बताया कि 1500 से अधिक 'माई भारत' स्वयंसेवी और अन्य इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

'माई भारत' युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता और व्यावहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है।

खडसे ने कहा, ''मैं भारत के युवाओं से अपील करना चाहूंगी कि वे नेताजी और वीर सावरकर के जीवन एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ें। मैं सभी से अंडमान की यात्रा करने का भी आग्रह करना चाहूंगी।'' उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति तीर्थाटन होगा।

मंत्री ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि प्रस्तावित नेताजी स्मारक इस द्वीपसमूह को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र में बदल देगा, क्योंकि लोग न केवल इसके समुद्र तटों के लिए बल्कि सेलुलर जेल के सामने अपना सिर झुकाने के लिए भी इस द्वीप पर आएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जनवरी, 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी को समर्पित प्रस्तावित स्मारक के मॉडल का वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया।

## मणिपुर के मूल समुदाय को अवैध आव्रजन के प्रति 'बहुत सतर्क' रहने की है जरूरत : एन बिरेन सिंह

**इंफाल/भाषा।** मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि राज्य के मूल समुदाय को अवैध आव्रजन के प्रति 'बहुत सतर्क' रहने की जरूरत है।

सिंह ने तामेंगलोंग जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कह कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्य के हर समुदाय का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा, ''असम और त्रिपुरा में अवैध प्रवासियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम उचित तरीके से जांच नहीं करेंगे तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। हम मूल निवासियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं है। सीमा पर कोई बाड़ नहीं है और न ही कोई सीमा सुरक्षा है। यहां तक कि अब भी इसकी (सीमा की) उचित देखभाल नहीं की जा रही है।'' सिंह ने कहा कि समुदायों के बीच विश्वास और सम्मान की कमी ने राज्य में अनिश्चितता पैदा कर दी है।

## 'बेटी बचाओ' की जगह 'अपराधी बचाओ' की नीति भाजपा ने क्यों अपनाई : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के 10 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा जश्न मनाए जाने के बीच बुधवार को दावा किया कि इस योजना के बजट का 80 प्रतिशत पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए यह सवाल किया कि ''बेटी बचाओ'' की जगह अपराधी बचाओ की नीति भाजपा ने क्यों अपनाई?

खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''बेटी बचाओ के 10 साल, मोदी जी से हमारे तीन सवाल। ''बेटी बचाओ'' की जगह अपराधी बचाओ की नीति भाजपा ने क्यों अपनाई? मणिपुर की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? हाथरस की दलित बेटी हो या उन्नाव की बेटी, या फ़िर हमारी चैंपियन महिला पहलवान, भाजपा ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण क्यों दिया?'' उन्होंने सवाल किया, ''क्यों देश में हर घंटे महिलाओं के ख़िलाफ़ 43 अपराध रिकॉर्ड होते हैं? हर दिन 22 अपराध ऐसे हैं जो हमारे देश के सबसे कमज़ोर दलित-आदिवासी वर्ग की महिलाओं व बच्चों के ख़िलाफ़ दर्ज होते हैं। मोदी जी लाल क़िले से भाषणों में कई बार महिला सुरक्षा पर बोल चुके हैं, पर कथनी और करनी में फ़र्क क्यों? क्या कारण है कि 2019 तक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के लिए आवंटित कुल धनराशि का क़रीब 80 प्रतिशत केवल मीडिया-विज्ञापन में ख़र्च हुआ?''

## केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा, कहा : 'छोटा सा लड़का, पंजाबियों को चुनौती दे रहा है'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं नई दिल्ली विधानसभा सीट से उनके प्रतिद्वंद्वी प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि ''छोटा सा लड़का (प्रवेश वर्मा) अब पंजाबियों को चुनौती देने चला है।'' एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि वर्मा और गृह मंत्री अमित शाह को पंजाबियों का ''अपमान'' करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।

वर्मा ने मंगलवार को केजरीवाल पर नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने के लिए 'आप' शासित पंजाब के आधिकारिक तंत्र और संसाधनों का ''दुरुपयोग'' करने का आरोप लगाया। उन्होंने निर्वाचन आयोग और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वर्मा ने कहा था, ''पंजाब में पंजीकृत हजारों गाड़ियां यहां घूम रही हैं। उन गाड़ियों में कौन हैं? यहां 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) की तैयारियां की जा रही हैं। क्या वे यहां कुछ बड़ा करने जा रहे हैं जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।'' केजरीवाल ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया और दावा किया कि ''वर्मा ने कहा है कि पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में देखी जा रही हैं और कोई नहीं जानता कि अंदर कौन बैठा है... और यह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले एक खतरा है।''

केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा, ''तो क्या सभी पंजाबी आतंकवादी, देशद्रोही और देश के लिए खतरा हैं?'' उन्होंने कहा, ''यह छोटा सा लड़का (प्रवेश वर्मा) अब दिल्ली और पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है।''

केजरीवाल ने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली आज जो कुछ भी है, उसमें उस समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। केजरीवाल ने कहा कि वर्मा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को देश और पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के पंजाबियों के पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दीं और पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों को अनगिनत यातनाएं सहनी पड़ीं।

## अरुणाचल में महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह लागू करेंगे: प्रदेश भाजपा प्रमुख

**ईटानगर/भाषा।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कलिंग मोयोंग ने बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी राज्य के अगले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून को अक्षरशः लागू करेगी। मोयोंग ने कहा कि इससे महिलाओं को शासन में भाग लेने के लिए एक मंच मिलेगा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2029 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में 20 महिला उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि, इस कानून को अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन में लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के बाद लागू किया जाना है। मोयोंग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया है कि वह महिला उम्मीदवारों को 'रसोई से बाहर आने' और 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार करने की खातिर प्रेरित करें। मोयोंग ने कहा, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के जीवनसाथी अगर पात्र नहीं हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा।

## गांवों में खेल अकादमियां खुले तो पैरा खिलाड़ियों के लिए अच्छा होगा: मुरलीकांत पेटकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर को लगता है कि उनके जमाने में गांवों में खेलों के लिए उत्कृष्ट सुविधायें नहीं होती थी और अब भी पैरा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की दरकार है इसलिये ध्यान शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में अकादमियां खोलने पर होना चाहिए।

जर्मनी में 1972 में हुए पैरालंपिक खेलों में मिली ऐतिहासिक जीत के 52 साल बाद पेटकर को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने इन खेलों में पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता और तीन विश्व रिकॉर्ड बनाए। इसके साथ ही वह पैरालंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बने। महाराष्ट्र में 1944 में जन्में पेटकर ने कहा, ''यह पुरस्कार पाकर बहुत खुश हूं। लेकिन गांवों में अब भी खेलों के लिए उतनी सुविधायें मौजूद नहीं हैं जैसे शहरों में होती हैं, विशेषकर पैरा खिलाड़ियों के लिए।'' अस्सी साल के पेटकर कहा, ''मेरे जमाने में देहात में कुछ सुविधा नहीं होती थी। अब भी जो खेल अकादमियां बन रही हैं वो शहरों में बन रही हैं। लेकिन गांवों में भी अकादमियां बनाओ। मेरा यही कहना है कि गांव में भी ऐसी उत्कृष्ट सुविधायें हों।''

## भारत चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी की पोशाक संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करेगा: बीसीसीआई सचिव सैकिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** भारतीय क्रिकेट टीम आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा 'पोशाक संबंधी सभी दिशानिर्देशों' का पालन करेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने बुधवार 'पीटीआई' से इस जानकारी को साझा करते हुए उन अटकलों को खारिज किया कि बोर्ड ने टीम की आधिकारिक जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम लिखने पर आपत्ति जताई थी।

चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया था और वह अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा।

सैकिया ने 'पीटीआई' से कहा, '' चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बीसीसीआई पोशाक से जुड़े आईसीसी के हर नियम का पालन करेगा।'' उन्होंने कहा, '' अन्य टीमें 'लोगो' और पोशाक से जुड़े नियमों के संबंध में जो भी करेंगी, हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे।''

सैकिया ने हालांकि यह नहीं बताया कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कप्तान के संवाददाता सम्मेलन और आधिकारिक फोटो शूट सहित आईसीसी के टूर्नामेंट पूर्व कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा, ''रोहित शर्मा आईसीसी मीडिया कार्यक्रमों के लिए पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, यह अभी भी तय नहीं है। ''

इससे पहले कुछ अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण बीसीसीआई ने अपनी जर्सी पर मेजबान देश का नाम नाम लिखने पर आपत्ति जताई थी। आईसीसी के किसी भी आयोजन में सभी टीमों के पोशाक पर मेजबान देश का नाम होता है। यह समझा जाता है कि 'लोगो' दिशानिर्देशों का पालन करने को लेकर कभी कोई संदेह नहीं था और बीसीसीआई ने वैश्विक संस्था के समक्ष इस पर चिंता नहीं जताई थी।

## गेंदबाजों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार बुमराह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**दुबई/भाषा।** भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बुधवार को जारी ताजा आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं जबकि रविंद्र जडेजा ने भी हरफनमौला खिलाड़ियों के वर्ग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और अंतिम बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट से पहले जनवरी में 907 अंक के साथ अब तक की सर्वोच्च आईसीसी रैंकिंग रेटिंग दर्ज करके इतिहास रचने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 908 अंक के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस (841) और दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा (837) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

पाकिस्तान के नोमान अली (761) मुल्तान में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में छह विकेट लेने के बाद शीर्ष 10 में पहुंच गये।

टेस्ट प्रारूप में शीर्ष-10 ऑलराउंडरों की सूची में कोई बदलाव नहीं हुआ जिसमें हरफनमौला रविंद्र जडेजा (400 रेटिंग अंक) शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसेन (294) और बांग्लादेश के मेहदी हसन (263) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

## सुविचार

यदि तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा, इसी तरह ब्रह्म ज्ञान लाभ कर लेने के बाद संसार में रहो तो तुम्हें कामिनी, कंचन की बाधा नहीं होगी।

## दक्षिण भारत राष्ट्रमत

# कैसे सुरक्षित बनें सड़कें?

भारत में सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब लोग इन हादसों में जान नहीं गंवाते। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने काफी कोशिशें कीं, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत का वाहन उद्योग अगले पांच साल में दुनिया में पहले स्थान पर होगा। इससे निश्चित रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर वाहन ज्यादा होंगे तो सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी ज्यादा होगी। हालांकि इसके लिए सिर्फ वाहनों की संख्या को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सड़कों की स्थिति, यातायात के नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार से वाहन चलाने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाने, उस दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, कार चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने जैसे अनगिनत कारण हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि काफी पढ़े-लिखे लोग भी यातायात के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए, तो जवाब मिलता है- 'कुछ नहीं होता ... यहां यातायात पुलिस तो नहीं है!' यातायात संबंधी नियमों का पालन पुलिस से बचने के लिए करना चाहिए या अपने और अन्य लोगों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए करना चाहिए? सबकुछ जानते हुए भी यातायात नियमों का आदतन उल्लंघन करने वालों के लिए बंबई उच्च न्यायालय का एक फैसला नज़ीर है, जिसके तहत साल 2017 में नाबालिग रहते हुए बिना हेलमेट और लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाने वाले एक व्यक्ति को चार रविवार तक अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने उसके खिलाफ मामला निरस्त कर दिया। उस व्यक्ति को तीन महीने के लिए शहर की पुलिस के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराना होगा।

वास्तव में कुछ लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करने में अपनी शान समझते हैं। इस तरह वे खुद के साथ दूसरों की जान भी संकट में डालते हैं। न उन्हें दुर्घटनाओं का डर होता है और न जुर्माने की फिक्र होती है। अलबत्ता उनमें से बहुत लोग अपने मोबाइल फोन पर अच्छा-सा कवर चढ़वाना नहीं भूलते। कुछ हजार रुपए के मोबाइल फोन की इतनी चिंता करते हैं, लेकिन अपने अनमोल जीवन को बचाने के लिए हेलमेट पहनने से परहेज करते हैं! ऐसे लोगों से नियम पालन करवाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। पुलिस की सख्ती, भारी जुर्माना जैसी बातें एक हद तक ठीक हैं, उसके बाद इनसे ज्यादा फायदा नहीं होता। जानबूझकर एवं बार-बार नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में कुछ 'सकारात्मक दंड' लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए- ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थान, गौशाला, अस्पताल, वृद्धाश्रम आदि में सेवा एवं स्वच्छता संबंधी कार्य सौंपे जाएं। जो दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाता, उसे मौके पर ही दो हेलमेट दे दिए जाएं। उनका मूल्य उससे जरूर वसूला जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 जनवरी से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पाए जाने पर पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं देने का फैसला भी सराहनीय है। अगर प्रशासन 'हेलमेट नहीं, तो ईंधन नहीं' के फैसले को सही ढंग से लागू कर पाया तो इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। इन दुर्घटनाओं के लिए कुछ यातायात पुलिसकर्मी भी जिम्मेदार हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे अनगिनत वीडियो मौजूद हैं, जिनमें ये कर्मी रिश्वत लेते हुए देखे जा सकते हैं। सरकारों को चाहिए कि वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मिसाल कायम करें। कुछ पुलिसकर्मी भी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं करते। उन पर कई गुणा ज्यादा जुर्माना लगाना चाहिए।

## ट्वीटर टॉक

महाकुंभ का महाउत्सव जहां विश्व को भारतीय संस्कृति की दिव्यता से पुनः चमत्कृत किए हुए है, वहीं इस प्रदर्शनी के चित्र ईश्वर और मानव के सांस्कृतिक संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रयागराज की भूमि पर अमर बलिदानी पूज्य चंद्रशेखर 'आज़ाद' का रक्त गिरा था।

**-गजेन्द्र सिंह शेखावत**

किसानों को 'झटका' देना, प्रताड़ित करना एवं उनके अधिकारों को छीनना भाजपा सरकारों की अघोषित नीति रही है। राजस्थान में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने एमएसपी पर बाजरा खरीद का वादा किया था लेकिन अब वादाखिलाफी करके उन्हें धोखा दे रही है।

**-गोविंद सिंह डोटासरा**

आज सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना एवं चिकित्सकों से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की।

**-दीया कुमारी**

## प्रेरक प्रसंग

# जलार्पण की पुण्यता

एकनाथ पुण्यवान एवं परोपकारी संत थे। एक बार वे कुछ साधुओं के संग हरकी पौड़ी से गंगाजल लेकर रामेश्वर में 'रामेश्वरम' भगवान पर जलार्पण करने जा रहे थे। दो माह में आधा रास्ता तय हो चुका था। आगे रेतीला इलाका था। संतों ने देखा कि प्यास का मारा एक गधा तपते रेत में पड़ा तड़प रहा था। टोली में एकनाथ सबसे पीछे थे। साधुओं को रुका देख उनसे पूछा, 'यहां क्यों रुक गए?' साधु बोले, 'गधा प्यास से छटपटा रहा है, परन्तु पानी कहां से लाया जाये?' हालांकि सब संतों के पास कांवड़ में गंगाजल रखा था, पर वह रामेश्वरम के लिए था। संत एकनाथ ने कंधे से कांवड़ उतारी और गंगाजल निकालने लगे। साधु बोले, 'अरे यह क्या कर रहे हैं? जो जल दो माह में ढोकर यहां तक लाये हो और जो रामेश्वरम में चढ़ाना है, जिसके निमित्त यह यात्रा हो रही है क्यों वह जल इसे पिला रहे हो?' द्यार्द्र हृदय एकनाथ उनकी बात को अनसुनी करके गधे को पानी पिलाने लग गए। संतों ने फिर प्रतिवाद किया, 'क्या जलांजलि का संकल्प अधूरा रखकर रामेश्वरम चलोगे?' एकनाथ ने हंसकर कहा, 'जरूर चलेंगे और देखेंगे कि रामेश्वरम में भगवान की प्यास इस चौपाये से ज्यादा दुरूह नहीं होगी। चिंता मत करो।

## सामयिक

# युद्ध विराम समझौते का ईमानदारी से पालन जरूरी

**ललित गर्ग**

> गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया जाना है। दरअसल, सात अक्तूबर 2023 को हमास के क्रूर हमलों में इस्राइल के बारह सौ लोग मारे गए थे और करीब ढाई सौ लोगों को हमास के लड़ाके सौदेबाजी के लिये बंधक बनाकर ले गए थे। साफ था कि इस अपमानजक घटना का इस्राइल प्रतिशोध लेगा, लेकिन संघर्ष करीब डेढ़ वर्ष तक चलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि, कुछ इस्राइली बंधक रिहा किए गए, कुछ युद्ध के बीच मारे गए, लेकिन बचे बंधकों की रिहाई का भारी दबाव नेतन्याहू सरकार पर लगातार बना रहा।

धयह शांतिपूर्ण विश्व संरचना के लिये सुखद ही है कि करीब डेढ़ वर्ष से जारी इस्राइल-हमास संघर्ष खत्म करने के लिये युद्धविराम पर सहमति बन गई है। लेकिन इस एवं ऐसे युद्धों ने ऐसे अनेक ज्वलंत प्रश्न खड़े किये हैं कि जब युद्ध की अन्तिम निष्पत्ति टेबल पर बैठकर समझौता करना ही है तो यह युद्ध के प्रारंभ में ही क्यों नहीं हो जाता? युद्ध भीषणतम तबाही, असंख्य लोगों की जनहानि एवं सर्वनाश का कारण बनता है तो ऐसी तबाही होने ही क्यों दी जाये? खेर देर आये दुरस्त आये, इजराइल और हमास ने बुधवार को युद्ध विराम समझौते के पहले मसौदे पर सहमति जताई, जो संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा एवं अहम कदम है। अन्य बातों के अलावा, 60-दिवसीय युद्ध विराम प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बंधकों को रिहा करना, सहायता बढ़ाना, नष्ट हो चुके फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण करना और हमलों को रोकना शामिल होगा। डेढ़ साल से अधिक समय के युद्ध के बाद, युद्ध विराम फिलिस्तीन के लोगों तथा हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के लिए बहुत जरूरी राहत है। इसी तरह रूस एवं यूक्रेन के बीच लम्बे समय से चल रहा युद्ध भी समाप्त हो, यह शांतिपूर्ण उन्नत विश्व संरचना के लिये नितांत अपेक्षित है। क्योंकि ऐसे युद्धों से युद्धरत देश ही नहीं, समूची दुनिया पीड़ित, परेशान एवं प्रभावित होती है। इस तरह युद्धरत बने रहना खुद में एक असाधारण और अति-संवेदनशील मामला है, जो समूची दुनिया को विनाश एवं विध्वंस की ओर धकेलने देता है। ऐसे युद्धों में वैसे तो जीत किसी की भी नहीं होती, फिर भी इन युद्धों का होना विजेता एवं विजित दोनों ही राष्ट्रों को सदियों तक पीछे धकेल देता, इससे भौतिक हानि के अतिरिक्त मानवता के अपाहिज और विकलांग होने के साथ बड़ी जनहानि का भी बड़ा कारण बनता है।

इस्राइल-हमास में पिछले डेढ़ साल से चल रहे युद्ध के विराम को एक अहम कामयाबी माना जा रहा है। भले ही इस समझौते के लिये अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बीच संघर्ष समाप्ति का श्रेय लेने की होड़ हो, लेकिन गाजा के लोग जिस मानवीय त्रासदी से जूझ रहे थे, उन्हें जरूर इससे बड़ी राहत मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रयासों व मध्यपूर्व के इस्लामिक देशों एवं भारत की बार-बार की गई पहल के बावजूद अब तक शांति वार्ता सिरे न चढ़ सकी थी। जिसकी कीमत करीब पचास हजार लोगों ने अपनी जान देकर चुकायी। इस युद्ध से गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में जो तबाही हुई है, उससे उबरने में दशकों लग सकते हैं।

निस्संदेह, इस्राइल व हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक समझौता यथार्थ में लागू होता न नजर आए, तब कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। संघर्ष में वास्तव में हमास के कितने लड़ाके मारे गए यह कहना कठिन है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों-महिलाओं ने युद्ध में जान गवांई। एक अनुमान के अनुसार गाजा संघर्ष में उपजी मानवीय त्रासदी में करीब बीस लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस्राइली हमलों में अस्पताल-स्कूल भी निशाना बने, जिन्हें शरणार्थियों की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। इस्राइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध अपराध तक के आरोप लगाए गए। बहरहाल, जब लंबे समय के बाद शांति की स्थितियां बन रही हैं तो विश्व समुदाय, शक्तिशाली राष्ट्रों व संयुक्त राष्ट्र का दायित्व बनता है कि समझौते की शर्तों को साफ नियत एवं नीति से क्रियान्वित किया जाये। ताकि मध्यपूर्व में स्थायी शांति एवं अमनचैन की राह मजबूत हो सके। निश्चित रूप से युद्ध शांति का विकल्प नहीं हो सकता। इस संघर्ष की शुरुआत भले हमास ने की हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत उन लोगों ने चुकाई, जो इसके लिये जिम्मेदार नहीं थे।

युद्ध के आघात से युद्धरत देशों के साथ समूची दुनिया प्रभावित हुई है। युद्ध के आघात से तात्पर्य युद्ध के दौरान होने वाली दर्दनाक घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक संकट और शारीरिक-भावनात्मक पीड़ा से है, जैसे कि हिंसा का शिकार होना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, या संघर्ष के कारण प्रियजनों को खोना। युद्ध सामाजिक विश्वास को तोड़ता है, सामाजिक सामंजस्य को कम करता है और सामाजिक एवं राष्ट्रीय पूंजी को नुकसान पहुंचाता है। सशस्त्र संघर्ष के बाद, समाज उपसमूहों में गहराई से विभाजित हो जाता है जो युद्ध विराम के समझौते के बावजूद बाद के दौर में एक दूसरे से डरते हैं और नफरत करते हैं और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार रहते हैं। युद्ध के आघात से पीड़ित लोगों में अक्सर दूसरे पक्ष के साथ मेल-मिलाप करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की इच्छा कम हो जाती है। कमजोर नागरिक समाज और कम सरकारी क्षमताएं लोगों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ बना सकती हैं और राज्य के बिगाड़ने वालों या राजनीतिक विरोधियों द्वारा आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। यह स्थिति अक्सर हिंसा के निरंतर चक्रों के लिए मंच तैयार करती है।

हालांकि, अक्तूबर, 2023 में हमास के हमले से आहत इस्राइल कई मोर्चों पर लगातार युद्ध से थक चुका है, लेकिन अभी भी अरब जगत उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। ऐसी आशंका इसीलिए भी है कि कई बार बातचीत अंतिम दौर पर पहुंचते-पहुंचते पटरी से उतरती गई है। बात और घात लगातार चलते रहे हैं। अब भविष्य में देखना होगा कि दोनों पक्ष समझौते के अमल के प्रति कितनी ईमानदारी से प्रतिबद्ध नजर आते हैं। हालांकि, अपने बंधकों की जल्द रिहाई को लेकर इस्राइल के विपक्षी राजनीतिक दलों व मंत्रिमंडल में भी मतभेद उभर रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद थक चुकी इस्राइली सेना को भी राहत देने की मांग की जाती रही है। बहरहाल, युद्ध विराम के प्रश्न पर इस्राइल व हमास के बीच सहमति से शांति की उम्मीदें प्रबल हुई हैं। जहां एक ओर अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन व नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए श्रेय ले रहे हैं, वहीं ईरान इसे फलस्तीनी प्रतिरोध की जीत बता रहा है।

अभी गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया जाना है। दरअसल, सात अक्तूबर 2023 को हमास के क्रूर हमलों में इस्राइल के बारह सौ लोग मारे गए थे और करीब ढाई सौ लोगों को हमास के लड़ाके सौदेबाजी के लिये बंधक बनाकर ले गए थे। साफ था कि इस अपमानजक घटना का इस्राइल प्रतिशोध लेगा, लेकिन संघर्ष करीब डेढ़ वर्ष तक चलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि, कुछ इस्राइली बंधक रिहा किए गए, कुछ युद्ध के बीच मारे गए, लेकिन बचे बंधकों की रिहाई का भारी दबाव नेतन्याहू सरकार पर लगातार बना रहा। संघर्ष में वास्तव में हमास के कितने लड़ाके मारे गए यह कहना कठिन है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों-महिलाओं ने युद्ध में जान गवांई। एक अनुमान के अनुसार गाजा संघर्ष में उपजी मानवीय त्रासदी में करीब बीस लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस्राइली हमलों में अस्पताल-स्कूल भी निशाना बने, जिन्हें शरणार्थियों की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। इस्राइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध अपराध तक के आरोप लगाए गए। निश्चित रूप से युद्ध शांति का विकल्प नहीं हो सकता। हालांकि, इस बात को लेकर शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस समझौते से फिलस्तीनी संकट का स्थायी समाधान हो सकेगा। इस युद्ध मसले का हल कूटनीति और आपसी बातचीत से ही निकालने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता भारत लगातार व्यक्त करता रहा है। युद्ध का अंधेरा मिटाने, शांति का उजला करने एवं अहिंसा-सहजीवन की कामना ही भारत का लक्ष्य रहा है। इसीलिये भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार युद्ध विराम की कोशिश करते हुए दोनों ही देशों को दिशा-दर्शन देते रहे हैं। इसी तरह रूस एवं यूक्रेन में भी युद्ध-विराम की अपेक्षा है। बड़े शक्तिसम्पन्न राष्ट्रों को इस युद्ध को विराम देने के प्रयास करने चाहिए। जब तक रूस के अहंकार का विसर्जन नहीं होता तब तक युद्ध की संभावनाएं मैदानों में, समुद्रों में, आकाश में तैरती रहेगी, इसलिये आवश्यकता इस बात की भी है कि जंग अब विश्व में नहीं, हथियारों में लगे।

## जयंती पर विशेष

# साहसी व पराक्रमी योद्धा थे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

**रमेश सर्राफ धमोरा**

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा दिया गया जय हिन्द का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा का नारा भी उनका उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। आजादी की जंग में प्रमुख भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को 127 वीं जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका पूरा जीवन ही साहस व पराक्रम का उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी नौवीं संतान और पांचवें बेटे थे। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेंशॉव कॉलेजिएट स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेजिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। उनको उन्होने इंग्लैंड के केंब्रिज विश्वविद्यालय से सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था।

1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने सिविल सर्विस की सरकारी नौकरी छोड़ कर कांग्रेस से जुड़ गए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झण्डे दिखाये। कोलकाता में नेताजी ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिये कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम आठ सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष बोस उसके एक सदस्य थे। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे तभी पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। जब सुभाष बोस जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने सरदार भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियों को रिहा करने से साफ इन्कार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिये गांधी जी ने सरकार से बात तो की परन्तु नरमी के साथ। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधीजी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें। लेकिन गांधीजी अपना वचन तोडने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार द्धारा भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गयी। भगत सिंह को बचा नहीं पाने पर सुभाष बोस गांधीजी और कांग्रेस से बहुत नाराज हो गये।

1930 में सुभाष कारावास में रहते हुये ही कोलकाता महापौर का चुनाव जीतने पर सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गयी। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबियत फिर से खराब होने पर सुभाष इलाज के लिये यूरोप चले गये। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष इटली के नेता मुसोलिनी से मिले। जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया।

1938 में गांधीजी ने कांग्रेस के हरिपुरा वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था मगर उन्हें उनकी कार्यपद्धति पसन्द नहीं आयी। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतन्त्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाये। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था। परन्तु गांधीजी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का वक्त आया तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाये जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा। लेकिन गांधीजी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधीजी ने अध्यक्ष पद के लिये पट्टाभि सीतारमैया को चुना। बहुत बरसों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिये चुनाव हुआ। चुनाव में नेताजी सुभाष को 1580

मत व सीतारमैय्या को 1377 मत मिले। गांधीजी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गये। गांधीजी ने पट्टाभि सीतारमैय्या की हार को अपनी हार बबताया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की अनीता नाम की एक बेटी भी हुई।

जर्मनी जाकर नेताजी हिटलर से मिले। 1943 में उन्होने जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वह जापान पहुंचे। जापान से वह सिंगापुर पहुंचे। जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया लक्ष्मी सहगल जिसकी कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चन्द्र ने सशक्त क्रान्ति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। आजाद हिन्द फौज के प्रतीक चिह्न पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया। खून भी एक दो बूँद नहीं इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाये और उसमें मैं ब्रिटिश साम्राज्य को डूबो सकूं। 1944 को आजाद हिन्द फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान आजाद हिन्द फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिये नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंदमान और निकोबार द्वीप जीत लिये। यह द्वीप आजाद-हिन्द सरकार के नियंत्रण में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इंफाल और कोहिमा पर आक्रमण किया। लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिन्द रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से नेताजी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिये उनका आशीर्वाद भी मांगा। आजाद हिन्द फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका। किन्तु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारत में सेना के बल पर शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतन्त्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। विश्व इतिहास में आजाद हिंद फौज जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। जहां 30-35 हजार युद्ध बंदियों को संगठित, प्रशिक्षित कर अंग्रेजों को पराजित किया। पूर्व एशिया और जापान पहुंच कर उन्होंने आजाद हिन्द फौज का विस्तार करना शुरू किया। रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया भाषण सदैव के लिए इतिहास के पत्रों में अंकित हो गया। नेताजी की मृत्यु के संबध में विवाद बना हुआ है कि 18 अगस्त 1945 के बाद का सुभाषचन्द्र बोस का जीवन-मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

# योगी ने मंत्रियों संग त्रिवेणी में किया अमृत स्नान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

महाकुंभ नगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाकुंभ के अवसर पर पतित पाविनी गंगा,श्यामल यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में अपने मंत्रिमंडल के साथियों के संग पवित्र डुबकी लगायी और प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद योगी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ संगम स्थली पहुंचे और पवित्र डुबकी लगायी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सभी कैबिनेट मंत्री योगी के साथ मौजूद थे। एक गोल घेरे में सभी ने संगम में डुबकी लगायी और सूर्य देवता को जल अर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रफुल्लित नजर आये और सभी साथियों के संग जल क्रीड़ा भी की।

उन्होने इस अवसर पर फोटोग्राफरों को भी निराश नहीं किया और उनके कहने पर विभिन्न कोणों से फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के स्नान के दौरान घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार वातावरण में भक्तिरस का समागम कर रहा था।

प्रयागराज में बुधवार को 45 दिवसीय महाकुंभ मेला के दसवें दिन गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु जाते हुए।

# महाकुंभ नगर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रयागराज के लिए दो नए सेतु को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

महाकुंभ नगर। महाकुंभ नगर के अरैल में त्रिवेणी संकुल में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर दो नए सेतु समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रयागराज में सलोरी और हेतापट्टी के बीच गंगा नदी पर नया सेतु बनाने और यमुना नदी पर बने 'सिग्नेचर पुल' के समानांतर एक नया सेतु बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की अपनी आंतरिक यातायात की चुनौतियां हैं। गंगा नदी पर नया छह लेन का सेतु बन रहा है जो समय रहते पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुंभ में ढांचागत विकास का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि नए निवेश के कुछ प्रस्ताव यहां आए हैं जिनके लिए इच्छा पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) यहां जारी किए जा रहे हैं। इनमें मिर्जापुर में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश, एक मुरादाबाद और दो अन्य जिलों में निवेश का प्रस्ताव शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रहे बलरामपुर में उन्हीं के नाम पर केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि बागपत, हाथरस और कासगंज में पीपीपी (सार्वजनिकनिजी साझेदारी) मोड पर नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर प्रदेश के 62 आईटीआई (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के लिए पांच 'सेंटर ऑफ इन्नोवेशन, इनवेंशन व इनक्यूबेशन ट्रेनिंग सेंटर' की स्थापना के बारे में भी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि बैठक में प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के नगर निगमों के बांड जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया, अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम के बांड जारी किए थे जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रयागराज नगर निगम एक सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के लिए बांड जारी करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक विकास क्षेत्र हम विकसित करेंगे।

इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार करेंगे जो प्रयागराज से मिर्जापुर और वहां से भदोही होते हुए काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा।

उन्होंने कहा, इसके अलावा, वाराणसी और चंदौली से होते हुए यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जुड़ेगा। ढांचागत विकास की दृष्टि से जिस तरह से हम प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र को विकसित करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी–विंध्य विकास क्षेत्र को नीति आयोग के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये विकास क्षेत्र ना केवल पर्यटन की दृष्टि से, बल्कि आर्थिक उन्नयन और रोजगार सृजन की दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि चित्रकूट से प्रयागराज को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई।

# मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर हजारों विदेशी भक्त लगाएंगे पावन त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

महाकुंभ मगर। महाकुंभ नगर में 29 जनवरी को होने जा रहे मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ लोगों के पावन त्रिवेणी के तट पर पहुंचने का अनुमान है जिनमें विदेशी श्रद्धालु भी होंगे। आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाला अमृत स्नान प्रयागराज महाकुंभ में श्रृद्धालुओं के सैलाब को लेकर नया कीर्तिमान दर्ज करने जा रहा है। प्रशासन के दावे के मुताबिक इस स्नान पर्व में सात से 10 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के महाकुंभ पहुंचने का अनुमान है जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन के साथ साथ साधु संतों के शिविरों में भी इस पावन अवसर पर आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी बताते हैं कि अकेले उनके शिविर में इस पुण्य पर्व पर फ्रांस, इटली, जापान और रूस से 5000 से अधिक विदेशी भक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है। त्रिवेणी में अमृत स्नान के लिए ये सभी लोग 24 जनवरी से आना शुरू हो जाएंगे।

विश्व बंधुत्व का भाव भारतीय संस्कृति का मूल है और प्रयागराज महाकुंभ में पायलट बाबा के शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानंद जी के शिविर में इसकी झलक देखने को मिल रही है। यहां युद्धरत देशों यूक्रेन और रूस के नागरिक एक ही मंच पर एक साथ अपने गुरु के सानिध्य में विश्व शांति के लिए शिवनाम का जाप कर रहे हैं। रूसी के नागरिक एंड्री खुद को भगवान शिव का भक्त बताते हुए कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाना एक रहस्य जैसा अनुभव है। वहीं, यूक्रेन से आए ओली सिमोवा भी स्वामी विष्णुदेवानंद जी के शिविर में एंड्री के साथ मिलकर शिवनाम का जाप करते हैं। सिमोवा बताते है कि दस साल से वह भारत आ रहे हैं और गुरु के मार्गदर्शन में भगवान शिव का ध्यान करते हैं।

प्रयागराज में बुधवार को महाकुंभ मेला 2025 के दसवें दिन गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर अपने शिविर में साधु।

RNI No. : TNHIN/2013/52520
Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016
posted at Patrika Channel,
Egmore RMS, Chennai-8

जीव को प्रबल पुण्याई से ही दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है। उसमे भी हमारा सौभाग्य है कि हम जिनवाणी श्रवण करने हेतु यहा उपस्थित हुए है। कर्मवाद के सिद्धांत से अपने- अपने कर्मानुसार हर जीव सुख- दुःख भोगता है। सुख- दुःख का कर्त्ता जीव स्वयं ही है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मे न गवांते हुए संसार से मुक्ति ही अपना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इस पंचम आरे मे मुक्ति संभव नही है।

# अतिक्रमण से त्रस्त है बस टर्मिनल ब्रॉडवे, यात्री हो रहे है परेशान

## प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही का निवेदन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। इन दिनों महानगर का दूसरा सबसे बड़ा बस टर्मिनल है ब्रॉडवे, बदहाली में चल रह है। इस ब्रॉडवे टर्मिनल से शहर व उपनगरों के लिए रोजाना सैंकड़ों बसे आवागमन करती है। इन दिनों यह बस टर्मिनल अतिक्रमण से ग्रस्त है। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को बस टर्मिनल का अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार आदेश एवं फटकार लगाई है, इसके बावजूद सरकार के अधीनस्थ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन इस बस टर्मिनल से अतिक्रमण हटाने में नाकामयाब रही है। यात्रियों को अतिक्रमण के कारण बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्यक्षकर्ता ने बताया कि अतिक्रमण इतना है कि धूप से बचने के लिए यात्रियों को जगह तक नहीं मिलती। कहीं सब्जी, फल, फुटकर आइटमों के ठेले लगे है तो कहीं जमीन पर बैठकर महिलाएं दुकान खोलकर रखी है। एमटीसी कर्मियों को अतिक्रमण के कारण बसों की आवाजाही में भी बेहद मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार तो बस ड्राइवर एवं अतिक्रमणकारियों के बीच कहासुनी भी हो जाती है। नागरिकों का निवेदन है कि प्रशासन तुरंत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाए ताकि यात्रियों को आवाजाही व चलने में सहूलियत हो। यह जानकारी विष्णुदेव मंडल ने दी।

# अर्जित 'ज्ञान' समाज एवं देश के विकास में समर्पित हो : राज्यपाल गहलोत

## कुवेम्पु विश्वविद्यालय ने आयोजित किया 34वां दीक्षांत समारोह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिव्वगोगा। शहर के कुवेम्पु विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में राज्य के राज्यपाल थावरचन्द गहलोत शामिल हुए तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विद्यार्थियों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग न केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि समाज, देश और पर्यावरण की भलाई के लिए भी करने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक होता है। यह न केवल कड़ी मेहनत और समर्पण का उत्सव है, बल्कि आपके सपनों की उड़ान की शुरुआत भी है। उन्होंने कहा कि यह दीक्षांत समारोह यह संदेश देता है कि आप शिक्षा के पथ से अनुभव और कर्म के पथ पर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से भरी दुनिया आपके सामने है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लाती है। शिक्षा सिर्फ करियर बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मानवता के उत्थान में अपना योगदान सुनिश्चित करने का साधन है।

राज्यपाल गहलोत ने कहा कि विद्यार्थियों सबसे पहले सपने देखें और उन्हें पूरा करने का साहस करें। बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से उन्हें हासिल करें। दूसरा, प्रकृति और समाज के प्रति संवेदनशील रहें। अपने कार्यों और प्रयासों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का संकल्प लें। तीसरा, सीखते रहें। राज्यपाल ने सलाह दी कि शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, यह जीवन के हर चरण में आपका मार्गदर्शन करती रहती है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के युग में युवा पीढ़ी का योगदान मानव जाति को एक नई दिशा देता है। शैक्षणिक सफलता तो बस एक यात्रा की शुरुआत है। अपने काम से समाज को गौरवान्वित करें और आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपने माता-पिता, शिक्षकों और इस विश्वविद्यालय के हमेशा आभारी रहें।

समाज कल्याण, सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय हित में उनके प्रयासों के लिए प्रोफेसर सीएस उन्नीकृष्णन, डी. नागराज और कागोडु थिमप्पा को दीक्षांत समारोह में मानद उपाधियों से सम्मानित करना खुशी की बात है। उन्होंने उन्हें बधाई देते हुए समाज के प्रति अपनी सेवा जारी रखने का अनुरोध किया।

दीक्षांत समारोह में हैदराबाद विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त चांसलर प्रो. राम रामास्वामी, चांसलर सरथ अनंतमूर्ति और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

## मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मदुरै जिले के मेलूर निर्वाचन क्षेत्र के वल्लपट्टी, अरितापट्टी, कितारिपट्टी और नरसिंहपट्टी के किसानों के एक समूह ने विभिन्न मांगों को लेकर तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलै के नेतृत्व में नई दिल्ली में केन्द्रीय खान मंत्री किशन रेड्डी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री मुरुगन से मुलाकात की। किसानों ने मंत्रीद्वय से मेलूर निर्वाचन क्षेत्र में टंगस्टन खदान स्थापित करने के समझौते को रद्द करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने का निवेदन करते हुए ज्ञापन सौंपा। मंत्रियों ने हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

# 'ज्ञान सहित किया गया तप ही श्रेष्ठ तप है'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, अलसूर के तत्वावधान में महावीर भवन में आयोजित प्रवचन में विनयमुनिजी खींचन ने कहा कि तपस्या मात्र कर्म निर्जरा के उद्देश्य से करनी चाहिए। तपस्या में इस लोक से वाह वाही और पर लोक के सुख की भी कामना नहीं करनी चाहिए। ज्ञान सहित किया गया तप ही श्रेष्ठ तप है। श्रद्धा, चारित्र और ज्ञान के गुण से तपस्या शोभित होती है। विनयमुनिजी ने कहा कि अहिंसा हमारा प्रधान सिद्धांत है। विवेक से अहिंसा पुष्ट होती है। घर में बढ़ते साधनों के साथ सूक्ष्म हिंसा बढ़ रही है। हमारे पूर्वज हर कार्य में यतना रखते थे। और बच्चों में भी यतना के संस्कार भरते थे। हिंसा बढ़ती है तो संवेदनाएं मंद पड़ जाती हैं। हम मन को व्यवस्थित करना सीखें। पुण्य से मन मिलता है और मन की गति भी सबसे तेज होती है। यदि मन को वश में करना नहीं सीखा तो भविष्य में तनाव एक भयंकर सामाजिक समस्या बन जाएगी। संघ मंत्री अभयकुमार बांठिया ने सभा का संचालन किया। अध्यक्ष धनपतराज बोहरा ने सभी का स्वागत किया।

# तमिलनाडु मारवाड़ी सम्मेलन के नेत्र जाँच शिविर में 92 लोग हुए लाभान्वित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन कोलकाता की दक्षिण प्रांतीय शाखा तमिलनाडु मारवाड़ी सम्मेलन ने एमएन आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में नेत्र जाँच शिविर का आयोजन रणजीत डॉ योगिता शाह परिवार द्वारा संचालित अविशा स्माईल्स परिसर में किया गया।

महामंत्री मोहनलाल बजाज ने बताया कि इस शिविर में एमएनआई हास्पिटल के डाक्टरों की टीम ने नेत्र जाँच की सेवाएँ प्रदान की। सहमंत्री अजय नाहर ने बताया कि शिविर में कुल 92 लोगों ने जाँच कराई। 23 जरुरतमंद लोगों को चश्मे वितरित किए गए । 4 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। शिविर में अध्यक्ष अशोक केडिया, पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल, मुरारीलाल सौंथलिया व कृष्णकुमार नथानी आदि उपस्थित थे।

# प्रभु रामचंद्र को समर्पित भजन संध्या 26 को

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के मूलकड़े के चंद्रप्रभु कॉलोनी स्थित कुमावत समाज भवन में 'एक शाम प्रभु श्री रामचन्द्रजी के नाम' का भक्तिमय रात्रि जागरण 26 जनवरी को रात्रि 7.30 बजे से श्री राम सेना चेन्नई के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। सेना के मदनलाल दुबलदिया (धनेरिया) बताया कि इिस भजन संध्या में बिंदु कुमावत एवं प्रकाश नागौरी (खिंयाला) भजनों की गंगा बहाएंगे। कार्यक्रम में कुमावत समाज के अध्यक्ष घेवराराम पिलौदिया सहित उनकी टीम विशेष रुप से उपस्थित रहेगी। आयोजन को लेकर श्री राम सेना के सदस्य विशष तैयारियों में जुटी है।

# अमेरिका ने अगर शुल्क लगाया तो कनाडा भी पीछे नहीं रहेगा: कनाडा के नेता

टोरंटो। कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और देश के तेल संपन्न अल्बर्टा प्रांत के नेता डैनियल स्मिथ को भरोसा है कि कनाडा अमेरिका के 25 प्रतिशत शुल्क से बच सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह एक फरवरी से कनाडा पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। जस्टिन ट्रूडो और डैनियल स्मिथ ने तर्क दिया कि कनाडा ऊर्जा महाशक्ति है, जिसके पास तेल और महत्वपूर्ण खनिज भंडार है और ट्रंप के संकल्प के मुताबिक अमेरिका को ''तेजी से बढ़ती'' अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कनाडा की इस संपदा की आवश्यकता होगी। कनाडा में विनिर्माण और ऑटोमोबाइल के केंद्र, ओंटारियो के प्रमुख डग फोर्ड ने कहा कि कारोबारी मुकाबला 100 प्रतिशत होने वाला है। फोर्ड ने 'एसोसिएटेड प्रेस' (एपी) के साथ साक्षात्कार में कहा, ''ट्रंप ने कनाडा पर 'आर्थिक युद्ध' की घोषणा की है और हम अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए हर वह तरीका आजमाएंगे जो हम आजमा सकते हैं।'' ट्रूडो ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो कनाडा जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जिक्र किया कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन वे मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू करने में सफल रहे थे।

# आईटीआई लि. को महाराष्ट्र में आपले सरकार सेवा केंद्र के लिए 167 करोड़ रु. का अनुबंध मिला

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से एक बड़ा अनुबंध हासिल किया है। इसमें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र और अमरावती क्षेत्र की ग्राम पंचायतों (एएसएसके-जीपी) में आपले सरकार सेवा केंद्र (एएसएसके) की स्थापना, संचालन, रोलआउट और कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है। इस अनुबंध में एक वर्ष के लिए सिस्टम के मेंटिनेंस को भी शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट की लागत लगभग 167 करोड़ रुपए है, जिसमें एएसएसके-जीपी में टेक्निकल मैनपावर की तैनाती की लागत और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खर्च भी हैं। इस अनुबंध पर आईटीआई लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश राय ने कहा, 'हमें महाराष्ट्र सरकार से यह नया ऑर्डर पाकर बहुत खुशी हो रही है, जिसके तहत हम डिजिटल माध्यम से कुशल नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार की मदद करेंगे। इससे पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करके राज्य के समग्र ग्रामीण विकास को सक्षम बनाया जा सकेगा।' राय ने कहा, 'आपले सरकार सेवा केंद्र जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों के जरिए नागरिकों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से सेवाओं की पेशकश से फायदा पहुंचाया जा सकता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

## गीत

### मन में अपना गाँव लिए

कुछ लम्हों की मीठी यादें
कुछ लम्हों के दाँव लिए,
घूम रहे हैं विदेश में हम
मन में अपना गाँव लिए।

आँगन की माटी की ख़ुशबू
खलिहानों की पुरवाई,
ले आए हैं गाँठ बाँधकर
पड़ोसियों की पहुँनाई,
नदी, सरोवर, पनघट, मंदिर
आम्रकुंज की छाँव लिए।

पहने देसी वस्त्र हमेशा
खाए नित देसी व्यंजन,
जिस वन में कुछ रोज़ गए हम
वही बन गया वृंदावन,
पाँच सितारा होटल में भी
ठहरे अपना ठाँव लिए।

किसी बात पर आहें भरना
किसी बात पर मुस्काना,
भुला नहीं पाये हैं अबतक
पनिहारिन का शरमाना,
चूड़ी ,कंगन, बिंदिया, पैजन
पाँहुर वाले पाँव लिए।

माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग'
मो. 9424141875

# भाग्यवंती बनीं चन्दनबाला महिला मण्डल की अध्यक्ष, सरला बनीं मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय चन्दनबाला महिला मण्डल की साधारण सभा आशापुरा मंदिर में सम्पन्न हुई। अध्यक्षा आशाबाई मेहता ने सभी का स्वागत किया। मंत्री रोशनबाई पिछोलिया ने मंडल की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि मंडल ने 18 नेत्र जांच शिविरों में 600 लोगों का निशुल्क आपरेशन करवाया। पिछोलिया ने तप अनुमोदना, ओली तप, मानवसेवी कार्यों, गुरुदर्शन यात्रा की विस्तार से जानकारी दी।

कोषाध्यक्षा मेहताबाई ने आयव्यय की जानकारी दी। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से भाग्यवंती जैन को अध्यक्ष एवं सरलाबाई रांका को मंत्री बनाया। बैठक में सुशीलाबाई लुंकड़ को संघ नायिका का पदभार सौंपा गया। इस कार्यक्रम में मंडल की अनेक सदस्याएं उपस्थित थीं। भाग्यवंती बाई ने अंत में मांगलिक श्रवण कराया।

# 'मानसिक शांति के लिए मंत्रजाप और ध्यान जरुरी'

हासन/दक्षिण भारत । बुधवार को सुबह आदिनाथ जैन भवन में संगीतमय मंत्रजाप और साधना की विधियों का मार्गदर्शन देते हुए आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि मानसिक शांति के लिए ध्यान और मंत्रजाप अत्यंत आवश्यक है। ये मन की खुराक है। जिस प्रकार तन को स्वस्थ रखने के लिये पौष्टिक भोजन करना पड़ता है, उसी प्रकार मन को शांत और स्वस्थ रखने के लिये ध्यान व मंत्रजाप करने चाहिए। आधुनिक युग का मनुष्य अधिक से अधिक भौतिक साधन-सामग्रियों में उलझकर बेहद परेशान हो रहा है। जीवन का अंत है, पर उसकी इस दौड़ का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। जितने साधन और जितनी सुविधाएं हम अर्जित करते हैं, उतनी ही मानसिक शांति नष्ट होती जाती है। ध्यान और मंत्रजाप मानसिक शांति के प्रयोगसिद्ध अमोघ उपाय हैं। आकाश, पाताल और धरती, कोई कहीं भी पहुंचें, आखिरकार सभी को शांति और स्वस्थता के लिए ध्यान की शरण में आना हैं, मंत्रजाप से तारतम्यता प्राप्त करनी है। शाम के सत्र में आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि मन की भूख असीम है। उसे नियंत्रित कर जीवन को श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता से ओतप्रोत बनाना चाहिये। वही श्रेष्ठ शकुन हैं। गणि पद्मविमलसागर ने बताया कि आध्यात्मिक अभिरुचि और साधना के बिना साधनों की कोई महत्ता सिद्ध नहीं होती। जहां साधन हार जाते हैं, वहां साधना जीवन को सही मार्ग देती है। गृहस्थ जीवन में दोनों का संतुलन साधकर ही आप सफल हो सकते हैं।

जैनाचार्य ने कहा कि तीन या तीन से अधिक स्वरों और व्यंजनों के जोड़ से बीजमंत्रों का निर्माण होता है। वे ध्वनिविज्ञान के अद्भुत आविष्कार हैं। ऊँ, ह्रीं, श्रीं आदि बीजमंत्र न सिर्फ शरीर के अलग अलग केंद्रों को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे भारतीय मंत्रसाधना के प्राणतत्व हैं।

प्राचीनकाल से इन बीजमंत्रों के हजारों-लाखों सफल प्रयोग हुए हैं। भौतिक संपादनों के बीच हर मनुष्य को ध्यान के प्रयोग और इष्टमंत्रों के जाप कर जीवन को निरापद और आनंदमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। शांति से जीने का यही रास्ता है। देर-सबेर सभी को इस मार्ग पर आना है। गुरुवार को प्रातः आदिनाथ मंदिर में मंत्रों और मुद्रा विधानों के साथ विविध जड़ीबूटियों और औषधियों से संगीतमय अभिषेक होगा।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.